# हिन्दुस्तान और ब्रिटेनका आर्थिक लेन-देन



लेखक

जे. सी. कुमारप्पा

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद

# नाम

लॉर्ड क्लाअिवको आम तौरपर भारतमें अंग्रेज़ी राजकी नींव डालनेवाला माना जाता है ।

बचपनमें रॉबर्ट क्लाअिव (१७२५–१७७४) से अुसके शिक्षक बड़े दुःखी और निराश रहते थे । वह १८ सालकी अुम्रमें अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी नौकरीमें 'लेखक'के कामपर आया था। ३५ वर्षकी आयुमें जब वह अिंग्लैण्ड लौटा, तब अुसके पास ३ लाख पौण्डकी सम्पत्ति जमा हो गअी थी और अुसे अपनी माफ़ी (जागीर) से २७ हज़ार पौण्ड सालानाकी खालिस आमदनी थी । सरकारी अर्थ-नीति और अीमानदारीके जो अुसूल अिस लुटेरे राजनीतिज्ञने अपने समयमें चलाये थे, वे आज तक भारत सरकारकी अर्थ-नीतिका मुख्य अंग बने हुअे हैं ।

अिस सदीके शुरूसे ही ब्रिटेनकी अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू अर्थ-नीति पर लॉर्ड केनीज़का ज़रूरतसे ज्यादा असर पड़ा है ।

ब्रिटेनकी सन्धियों, हर्जानेके दावों और लड़ाअीके ज़मानेके क़र्ज़ोंके लेन-देनमें जॉन मैनार्ड केनीज़ (१८८४–१९४६) का भारी हाथ रहा है । वही ब्रिटेनकी सुरक्षित सम्पत्तिका मूल्य गिरा देनेवाली नीतिके लिअे ज़िम्मेदार है । ब्रेटन वुड्स कान्फरेन्सका संचालन भी अुसीकी देखरेखमें हुआ था । ब्रिटेन और भारतसे सम्बन्ध रखनेवाली अर्थ-नीति पर अुसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है । यह असर लगभग ३४ साल पहले 'हिन्दुस्तानका सिक्का और अर्थ-नीति' (अिण्डियन करेन्सी ॲण्ड फाअिनैन्स) नामकी अुसकी किताबसे शुरू हुआ था ।

अिस नीतिके चलानेवालोंमें लॉर्ड क्लाअिवका नाम सबसे पहले आता है । हमें आशा करनी चाहिये कि लॉर्ड केनीज़के बाद यह परम्परा टूट जायगी ।

# दो शब्द

जब कोअी आदमी दूसरेके मालसे फ़ायदा अुठाना चाहता है और अैसी सम्पत्तिपर, जो अुसकी नहीं हो, बुरी नज़र डालता है, तो वह कअी तरक़ीबोंसे काम लेता है। जैसी अुसकी परिस्थिति होती है, वैसी ही अुसकी युक्ति होती है। (१) सबसे सीधा तरीक़ा धौंसका है। अिसके ज़रिये अपनी शिकारको भयभीत करके अुससे धन छीन लिया जाता है। (२) दूसरा अुपाय ग़बन है। अिसके ज़रिये मनुष्य दूसरेकी दी हुअी अमानतमें खयानत करता है। (३) अक्सर रोकड़िये लोग झूठे हिसाब बनाते हैं यानी खर्चेको पूँजीमें दिखाकर या रोज़मर्राके खर्चेको लम्बी मियादके खर्चोंमें बताकर जो रक़में अुठा ली जाती हैं या ग़लत तौरपर काममें ली जाती हैं, वे मालिककी छानबीनसे परे रखी जाती हैं। (४) अिसके सिवाय, नौकर अपने मालिकके क़ीमती सामानको लेकर कौड़ियोंमें गिरवी रख देता है; या (५) संरक्षक धरोहरकी सम्पत्तिको अपने काममें लेकर अुसका दुरुपयोग करता है। निजी सम्पत्तिके अितिहासमें दुष्टोंने जो जो आर्थिक अपराध किये हैं, अुनमेंसे कुछ नमूने ये हैं।

अंग्रेज़ोंका हिन्दुस्तानसे जो सम्बन्ध रहा है, अुससे ज़ाहिर होता है कि अिन सब क़िस्मकी बेअीमानियोंसे काम लेकर पूरा फ़ायदा अुठाया गया है और अिनके अलावा अिन लोगोंने कुछ नये हथकण्डे भी निकाले हैं।

विलायतसे अेक मण्डली हिन्दुस्तान आ रही है। ये लोग भारत सरकार और रिज़र्व बैंकके नुमाअिन्दोंसे हिन्दुस्तानके पौण्ड पावनेके बारेमें 'बातचीत' करेंगे। अिस मण्डलीके मुखिया हैं ब्रिटिश खज़ानेके दूसरे मन्त्री सर विलफ्रिड अीडी और अुनके साथ बैंक ऑफ़ अिंग्लैण्डके डिप्टी गवर्नर मि० सी० अेफ० कबोल्ड, भारत मन्त्रीके दफ़्तरके अर्थ-

विभागके मुखिया मि० के० अेण्डर्सन और बैंक ऑफ अिंग्लैण्डके अेक्सचेंज कण्ट्रोल विभागके मि० पी० अेस० बील हैं ।

यह बता दूँ कि जिस पौण्ड पावने पर अिस मण्डलीका अिस वक़्त ध्यान लगा हुआ है, वह कअी अैसी अलग अलग रक़मोंके बाद बाक़ी निकला है, जो अंग्रेज़ी अधिकारके बादसे हमारे नाम लिखी गअी हैं, और कअी रक़में हमारे खातेमें जमा हुअी हैं ।

अिसलिअे ग्रेट ब्रिटेन और हिन्दुस्तानके बीच जो आर्थिक लेन-देन हुआ है, अुसके अितिहासकी भूमिकापर अेक नज़र डाल लेना दिलचस्पीसे खाली न होगा । अिससे पता लगेगा कि 'अिंग्लैण्डके शानदार महल' हिन्दुस्तानकी हड्डियोंसे बने हैं ।

१५ फरवरी, १९४७
मगनवाड़ी
वर्धा ( मध्यप्रान्त )

जे० सी० कुमारप्पा

# विषय-सूची


पृष्ठ

नाम . . . . ३

दो शब्द . . . ४-५

१. भूमिका . . . ७-१२

निजी अर्थ-व्यवहार, आधार आदमनी ७; सरकारी अर्थ-व्यवहार, आधार खर्चे ८; अुत्पादक और अनुत्पादक ऋण ८; बजट, कर्ज ९; राष्ट्रीय ऋण १०; सरकारी ऋण १०; नियंत्रण ११

२. अीस्ट अिण्डिया कम्पनी . . १२-१४

धौंसका ज़माना १२; ग़बनका ज़माना १३

३. विक्टोरियाका युग . . १४-३०

झूठे हिसाब बनाना १४; अफगान युद्ध १७; अीरानी युद्ध १८; ग़दर १९; अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी पूँजी और अुसका मुनाफा २०; ताज़की मातहतीमें २०; अेबीसिनिया, मिश्र, बर्मा, सूकिम वगैराकी बाहरी लड़ाअियाँ २१; फुटकर खर्चे २५; सालाना फौजी खर्चे २६; झूठे कर्ज़की रकमोंपर दिया गया ब्याज २९

४. मौजूदा ज़माना . . . ३०-३३

'दान'की युक्ति ३०; दुरुपयोग ३२

५. गिरवी रखकर कर्ज़ देनेका ज़माना . ३३-४०

काग़ज़ी कर्ज़ ३३; यू. किं. क. का. के कारनामे ३५; पौण्डके काग़ज़की बेसलामती ३६; क्रयशक्तिकी पायेदारी ३७; ग़बन ३९

६. अुपसंहार . . . ४०-४८

कांग्रेस सिलेक्ट कमेटीकी रिपोर्ट ४०; और लीजिये ४१; सरकारी ऋणोंपर गांधीजीका बयान ४५; चुकानेकी शक्ति ४६; जाँच पड़तालकी ज़रूरत ४७

# १

# भूमिका

खानगी अर्थ-व्यवहारमें व्यक्तिसे यह आशा रखी जाती है कि वह अपनी आमदनीके भीतर रहकर खर्च करेगा। वह आमदनी अुसे अपने आर्थिक कामकाजसे होती है। मामूली तौरपर अुसका खर्च अुतना ही होता है, जितनी अुसकी कमानेकी शक्ति होती है। आम तौरपर अगर वह कमाअीसे ज़्यादा खर्च करनेके लिअे क़र्ज़ करता है, तो अन्तमें अुसे अदालतमें जाकर दीवालियेकी दर्खास्त देनी पड़ती है। अगर वह आमदनीसे कम खर्च करता है, तो अुसकी खरीदनेकी ताक़त बढ़ती रहती है। अिसीको हम पूँजी कहते हैं। अुसे वह बचाकर भी रख सकता है और ज़्यादा पैदावारके लिअे अुधार भी दे सकता है। दोनों ही सूरतोंमें जहाँ आमदनी और खर्च बिलकुल बराबर नहीं होते, क़र्ज़ होता है। अुधार लेना होता है तब वह ऋण कहलाता है और देना होता है तब क़र्ज़ कहलाता है। हम देखते हैं कि खानगी अर्थ-व्यवहारमें आमदनीके अनुसार ही खर्च और क़र्ज़ तय होता है।

दूसरी तरफ़ सरकारी अर्थ-व्यवहारमें यानी राज्यके माली अिन्तज़ाममें, अेक हद तक फ़ैसला करनेवाली चीज़ आमदनी नहीं, खर्च होता है। यानी अगर हम यह अितमीनान करना चाहें कि सरकारी क़र्ज़ वाजिब तौरपर लिया गया है, तो हमें खर्चेकी अलग अलग मदोंकी जाँच-पड़ताल करके देखना होगा कि हरअेक मद देशकी आमदनीपर ठीक ठीक डाली गअी है या नहीं और कोअी फ़ज़ूलखर्ची तो नहीं की गअी है। फिर हमें यह जाँच करनी होगी कि नागरिकोंकी कितना कर देनेकी ताक़त है और देखना होगा कि ज़रूरी रुपया महसूल लगाकर वसूल हो सकता

है या नहीं। अितनी छानबीनके बाद हमें मालूम हो कि खर्चकी सारी रकमें देशकी भलाअीमें लगी हैं और वाजिब तौरपर लग सकती हैं और अगर नागरिक अब और कर नहीं दे सकते, तब अैसे हालातमें क़र्ज़ लेना बिलकुल मुनासिब होगा।

खानगी व्यक्ति अैसा नहीं करता, मगर राज्य पहले यह निश्चय करता है कि राजकाजके लिअे और राष्ट्र-निर्माणके कार्यक्रमके लिअे साल-भरमें कितना खर्च करना पड़ेगा, फिर वह आवश्यक रुपया ज़बरदस्ती वसूल करता है। अिसके लिअे नागरिकोंको हुक्म दिया जाता है कि वे करके रूपमें राज्यको चलानेके लिअे रुपया दें। अिस तरह सरकारी अर्थ-व्यवहारमें खर्च चलानेके लिअे आमदनी या लगान पैदा किया जाता है।

हमेशा यह सम्भव नहीं होता कि आमदनीसे ही खर्च चल जाय। अक्सर राज्यको अैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिनका फ़ायदा जनताको बरसों बाद होता है। अैसी हालतमें ज़ाहिर है कि आजके नागरिकोंसे यह कहना न्याय नहीं होगा कि वे आगेके लाभके लिअे सारा रुपया अिकट्ठा दे दें। मौजूदा पैदावारके लिअे यह बोझा अितना भारी हो सकता है कि पैदावार पर बुरा असर पड़े। अैसी सूरतमें आज जितने रुपयेकी ज़रूरत हो, वह राज्य अुधार ले ले और आयन्दा सालोंकी आमदनीमेंसे अुसे चुका दे। अिसके सिवा अचानक अैसे विशेष अवसर भी आ सकते हैं, जब कर लगानेपर निर्भर रहनेसे काम नहीं चल सकता। रुपयेकी तुरन्त आवश्यकता हो सकती है — जैसे लड़ाअी, अकाल या मरीके वक़्त। अैसे संकटकालमें सरकारको क़र्ज़का आसरा लेना पड़ता है।

पहली सूरतमें जहाँ करको अुन वर्षोंपर फैलाना होता है, जिनमें अुसका लाभ होनेवाला हो और जहाँ खर्च सुधारके कामोंमें लोगोंकी पैदावारकी शक्ति बढ़ानेके लिअे किया जाता है और अुससे लगाअी हुअी पूँजीपर मुनाफ़ा होता है, वहाँ अुसे 'अुत्पादक ऋण' कहते हैं।

दूसरी सूरतमें जहाँ ऋण किसी ज़रूरी खर्चके लिअे लिया जाता है और यह ज़रूरी नहीं कि अुससे पैदावारकी शक्ति बढ़े, वहाँ अुसे 'अनुत्पादक ऋण' कहते हैं।

सालभरका कार्यक्रम तय करते वक़्त बजट बनानेका काम आजकलके राजकाजमें बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है। अिससे जनताके सामने यह आ जाता है कि सरकार सालभरमें क्या क्या करना चाहती है और लोगोंको बता दिया जाता है कि अुनकी जेबसे क्या खर्च होनेवाला है। अच्छा बजट वह होता है, जिसमें आय-व्यय बराबर हों, और जहाँ और रुपयेकी ज़रूरत होती है, वहाँ वह बता भी देता है कि यह ज़ायद रक़म किस तरह वसूल की जायगी। करसे होनेवाली जितनी आमदनीकी आशा रखी जाती है वह जब खज़ानेमें देरसे पहुँचती दिखाअी देती है और खर्च तो करना ही पड़ता है, तब सरकारी हुण्डियोंके ज़रिये थोड़े दिनके लिअे क़र्ज़ ले लिया जाता है और बादमें जब कर वसूल हो जाते हैं, तब यह रुपया चुका दिया जाता है। अिन हुण्डियों और ऋणोंपर ब्याज लगता है और जब तक वह चुका नहीं दिया जाता, तब तक वह सरकारके साधारण खर्चमें शामिल हो जाता है।

जहाँ ब्याजकी रक़में देशके भीतरके ही लोगोंको दी जाती हैं, वहाँ लोगोंकी पैदावार देशमें ही रहती है और लोगोंकी शक्ति बहुत नहीं घटती। अुस हालतमें भी धनकी बुरी व्यवस्था होती है, क्योंकि कर वसूल तो किये जाते हैं ग़रीबोंसे और दिये जाते हैं क़र्ज़ देनेवालोंको, जो आम तौरपर अमीर होते हैं। जब ब्याज किसी ग़ैर मुल्कके शहरियोंको देना पड़ता है, तब क़र्ज़दार देशकी पैदावार गिरवी हो जाती है। जैसा जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है, ‘जो देश विदेशोंको नियमित रूपसे रुपया देता है वह जो कुछ देता है अुसे तो खो ही देता है, अिससे भी ज़्यादा नुक़सान अुसका यह होता है कि अुसे मजबूर होकर अपनी पैदावारके बदले विदेशी चीज़ें घाटेसे खरीदनी होती हैं।’ जब क़र्ज़ लेनेवाले मुल्ककी अैसी स्थिति हो कि क़र्ज़ देनेवाले देशका अर्थ-व्यवहार, चलन और विनिमयकी नीति भी अुसीके हाथमें हो और अुसके लिअे सामान खरीदना भी अुसके अधिकारमें हो, तब यह हालत भयंकर रूप धारण कर लेती है।

जब अैसी बड़ी रक़मोंकी ज़रूरत हो जो कभी चुकाअी नहीं जा सकतीं और जिनके लिअे सरकार अनिश्चित काल तक ब्याज देनेको तैयार

न हो, तो सरकार अपने विशेष अधिकारोंसे काम लेकर ज़ब्तीसे या पूँजी पर कर लगाकर साधन पैदा कर सकती है। ये रक़में आमदनीसे ज़्यादा तो होती हैं, मगर यह 'सरकारी ऋण' नहीं होता।

आमदनीसे साधारण ख़र्च ज़्यादा होनेपर बजटमें जो घाटा हो जाता है, अुसे ब्याज लगनेवाला ऋण मानकर पूँजी नहीं बना देना चाहिये।

क़र्ज़ लेकर सरकारी कामोंके लिअे रुपया अिकट्ठा करना अेक अैसी नअी बात है, जो थोड़े अर्सेसे ही चली है। यह अुस वक़्तसे शुरू हुअी है जबसे व्यापारिक अुधारका काम बहुत बढ़ा है। पहलेके राजा अुस रुपयेको काममें लेते थे, जो जमा रहता था या मन्दिरों या दूसरी सार्वजनिक संस्थाओंसे लिया जाता था।

जब सरकारी कामोंके लिअे ऋण अैसी सरकार लेती है जो जनताकी प्रतिनिधि हो, तो वे ऋण 'राष्ट्रीय ऋण' कहलाते हैं और बहुत करके अुसी देशके लोगोंसे लिये जाते हैं। जहाँ हुकूमत और रिआयाके बीच अैसा सम्बन्ध नहीं होता, वहाँ ये ऋण सिर्फ़ 'सरकारी ऋण' कहलाते हैं।

हिन्दुस्तानमें अंग्रेज़ोंके आनेसे पहले सरकारी ऋण-जैसी चीज़ कोअी नहीं जानता था। अुससे पहले कोअी राजा क़र्ज़ लेता था, तो वह अुसका अपना निजी मामला होता था और जिस प्रजापर वह राज करता था अुससे अुसका कोअी वास्ता न होता था। क्लाअिवके ज़मानेमें हिन्दुस्तान अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके मातहत था। यह अेक व्यापारिक जमात थी और अुसके पास कुछ ख़ास मुल्की अधिकार भी थे। देशकी हुकूमत मुनाफ़ेके ख़यालसे होती थी और पूँजी हिन्दुस्तानसे अिंग्लैण्डकी तरफ़ बराबर बही जा रही थी। हिन्दुस्तानी ऋणकी ज़रूरत न थी, क्योंकि ज़रूरतके अनुसार रुपया लूट-खसोटके सामन्तशाही नियमसे मिल सकता था। अितिहासके अिस कालमें अिंग्लैण्डकी माली हालत बहुत गिरी हुअी थी। ब्रूक्स अॅडमके कहनेके मुताबिक़[1] लगभग १७५०में "अिंग्लैण्डके लोहेके अुद्योगका पूरी

---

१. लॉ आफ़ सिविलाअिजेशन अॅण्ड डिके, पृ० ३१३

तरह पतन हो रहा था, क्योंकि अींधनके लिअे जंगल नष्ट किये जा रहे थे । अुस वक़्त अिस राज्यमें काम आनेवाला ४/५ लोहा स्वीडनसे आता था", और १७६०से पहले "लंकाशायरमें सूत कातनेवाली मशीनें लगभग अुतनी ही सीधी-सादी थीं जितनी हिन्दुस्तानमें थीं ।" आविष्कार करनेवाले बहुत थे, मगर आविष्कारोंको काममें लेनेके लिअे ज़रूरी रुपया नहीं था । दिल कल्पना कर दे और दिमाग़ तरकीब बता दे, तो भी अिन कल्पनाओंको व्यापारी पायेपर अमलमें लानेके लिअे हाथ न हों, आदमी न हों तो सब कुछ बेकार है । अिन विचारोंको काममें लानेके लिअे जिस पूँजीकी ज़रूरत थी, अुसके जुटानेका मौक़ा प्लासीकी लड़ाअीके बाद मिल गया ।

प्रतिनिधि सरकार न हो तो हुकूमतका फ़र्ज़ है कि अुसके हाथमें जो रुपया हो, अुसे धरोहर समझकर काममें ले । हिन्दुस्तानकी मौजूदा सरकारको अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी बनाअी हुअी परम्परा विरासतमें मिली और अुसने समयके अनुसार अपने तरीक़ोंमें अदल बदल भी कर लिये । फिर भी खज़ानेपर ठीक ठीक नियन्त्रण नहीं है, यद्यपि १८६१ से कठपुतली कौंसिलें बनाकर प्रतिनिधि शासनका ढोंग किया जा रहा है । १९०९ तक बजट अिन कौंसिलोंके अिलाकेमे बाहर था । अुसके बाद कुछ मदों पर बहस करनेकी अिजाज़त दी गअी और १९२० से सारे खर्चके लगभग २५% हिस्सेपर राय देनेका अधिकार दिया गया है । तबसे खज़ानेकी सत्ता अैसी कार्यकारिणीके हाथमें है, जो जनताके सामने ज़िम्मेदार नहीं है । पिछले साल जबसे अन्तरिम सरकार हुअी है तबसे बड़ी बड़ी आशाअें लगाअी गअी थीं, मगर अिसकी मौजूदा रचनामें अिसके "बायें हाथको यह पता नहीं चलता कि दाहिना हाथ क्या करता है ।"

# २
# अीस्ट अिण्डिया कम्पनी

## धौंसका ज़माना

बहुत शुरूके ज़मानेमें अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके आदमियोंने अिस देशमें खुली लूट मचाअी। प्लासीके बादके हालात बयान करते हुअे मैकॉले कहता है,[१] "अब कम्पनी और अुसके नौकरोंपर दौलतकी .खूब वर्षा हुअी। मुर्शिदाबादसे कलकत्तेके फ़ोर्ट विलियमको ८ लाख पौण्ड की कीमतके चाँदीके सिक्के नावोंमें भरकर भेजे गये और जो कलकत्ता कुछ ही महीनों पहले सुनसान पड़ा था, वह अब हरा भरा हो गया। हर अंग्रेज़ घरमें व्यापारके चमक अुठने और वैभवके निशान प्रगट होने लगे। रही बात क्लाअिवकी सो अुसका कोअी हाथ पकड़नेवाला ही न था। वह .खुद ही संयम रखता तो दूसरी बात थी।"

अिस तरह 'साम्राज्यकी अिमारत खड़ी करनेवाले' क्लाअिवको हिन्दुस्तानको लूटनेका और यूरोपके लिअे रुपया जुटानेका हक़ मिल गया। तीन साल बाद फटकेका करघा पैदा हो गया और फिर चार बरसमें हारग्रीवकी कातनेकी मशीन निकल आअी। १७६८में वॉटने अपना भापका अिंजन बना दिया। १७७९ में क्रॉमटनने 'खच्चर' मशीनका आविष्कार किया और शक्तिसे चलनेवाले करघेका १७८५ में हक़ पेटेण्ट हो गया। यहींसे अिंग्लैण्डमें अुद्योगकी क्रान्तिका और हिन्दुस्तानमें अुद्योगके पतनका आरम्भ हुआ। अिस तरह आविष्कारोंसे लाभ अुठानेके लिअे पूँजीकी जो ज़रूरत हुअी वह हिन्दुस्तानकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लूटसे पूरी की गअी।

[२]"शायद जबसे सृष्टि हुअी है, पूँजी लगानेके किसी काममें कभी अेतना मुनाफा नहीं हुआ जितना हिन्दुस्तानकी लूटसे हुआ, क्योंकि

---

१. अेसे ऑन लॉर्ड क्लाअिव, जिल्द ३ पृ. २४०

२. ब्रूक्स अेडम्स, 'लॉ ऑफ सिविलाअिज़ेशन अॅन्ड डिके', पृ. ३१७

लगभग ५० साल तक ग्रेट ब्रिटेनका कोअी प्रतिद्वन्द्वी नहीं रहा।" बर्क कहता है कि जहाँ १७५० में साहूकारोंकी १२ दुकानें भी नहीं थीं, वहाँ १७९० में हर मण्डीमें अेक-अेक बैंक खुल गया था।[१] "अिस तरह बंगालकी चाँदीके पहुँचते ही रुपयेका ढेर ही नहीं लग गया, बल्कि अुसका चलन भी तेज़ हो गया, क्योंकि १७५९में अेकदम बैंकने १० और १५ पौण्डके नोट जारी कर दिये और देशमें खानगी व्यापारिक कोठियोंने कागज़की बाढ़-सी बहा दी।" शायद प्लासी और वाटरलूके दरमियान हिन्दुस्तानके खजानेसे अंग्रेज़ी बैंकोंमें कोअी अेक अरब पौण्ड[२] धन भेजा गया होगा। अुस वक़्तकी रुपयेकी खरीद-शक्तिको देखते हुअे हम मुश्किलसे अन्दाज़ लगा सकते हैं कि यह रक़म कितनी बड़ी थी। यह ध्यान देनेकी बात है कि १८१५ में अिंग्लैण्डका सारा राष्ट्रीय ऋण सिर्फ़ ८६ करोड़ १० लाख पौण्ड था, जो अुससे पहलेके ५० सालकी हिन्दुस्तानकी लूटकी अन्दाज़िया रकमसे कहीं कम था।

## ग़बनका ज़माना

अुसके बाद हम माननीय अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके ग़बनके ज़माने पर आते हैं। कम्पनी अितनी मातबर थी कि वह धौंसके तरीक़ेसे काम नहीं ले सकती थी। अुसने यह किया कि वह लगानके रुपयेसे हिन्दुस्तानका माल खरीदकर यूरोप भेजती थी और वहाँ वह अुसके खातेमें बेचा जाता था।

अैसे हालातमें यह .क़ुदरती था कि जब ब्रिटिश ताजके प्रतिनिधि यानी अीस्ट अिण्डिया कम्पनीवाले अितनी भारी रक़में अिंग्लैण्ड भेज सकते थे, तब हिन्दुस्तानमें सरकारी ऋण लेनेका सवाल ही नहीं अुठता था। 'साम्राज्यकी अिमारत खड़ी करनेवालों'की बेहया लूटके अलावा, यह दूसरा अप्रत्यक्ष तरीक़ा अिसलिअे काममें लाया गया कि हिन्दुस्तानसे अिंग्लैण्ड रुपया हयादारीकी आड़में भेजा जा सके। अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी सरकारी आय करदाताओंके लिअे बिलकुल खर्च नहीं होती थी। अिस

---

१. ब्रुक्स अेडम्स, 'लॉ ऑफ सिविलाअिज़ेशन अॅण्ड डिके', पृ० ३१७

२. विलियम डिग्बीका 'प्रॉस्परस ब्रिटिश अिण्डिया', पृ० ३३

आयसे हिन्दुस्तानी माल खरीदकर यूरोपमें बिकनेके लिअे भेजा जाता था और अिस सौदेसे करदाताओंको कोअी मुनाफ़ा नहीं मिलता था। १७९३ और १८१२के बीचमें सरकारी आयकी जो औसत रक़म अिस तरह काममें ली गअी, वह सालाना १२० लाख पौण्डसे अूपर थी।[1]

३

# विक्टोरियाका युग

## झूठे हिसाब बनाना

जब हम विक्टोरियाके युगके पास पहुँचते हैं, तब ग्रेट ब्रिटेन अितना अीमानदार बन गया था कि वह क्लाअिवकी बेशर्म लूट या अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी बेपारी बेअीमानी-जैसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता था। वह लूटका माल तो लेना चाहता था, मगर अुसे अीमानदार और नेकनीयत दिखाअी देनेका बड़ा खयाल था। अब अुसने सारे हिसाब झूठे बनाना शुरू कर दिये।

अिसका ढंग यह था कि हिन्दुस्तानसे रुपया या माल तो न लिया जाय, मगर ब्रिटेनका खर्च हिन्दुस्तानके नाम लिख दिया जाय। नतीजा वही हुआ जो पहलेके दोनों तरीक़ोंसे हुआ था; यानी हिन्दुस्तानमें जो धन पैदा होता, वह अिंग्लैण्ड चला जाता और अुससे हिन्दुस्तानी अुत्पादकोंको कोअी फ़ायदा न होता। अिस तरह हमारा देश ग़रीब होता गया और ग्रेट ब्रिटेनके खज़ानेका बोझा हल्का होता रहा। जिसे आज 'हिन्दुस्तानका सरकारी ऋण' कहा जाता है, वह ज्यादातर अिसी तरह झूठी रक़में नामें लिख-लिखकर बनाया गया है।

हिन्दुस्तानका कोअी 'राष्ट्रीय ऋण' तो नहीं था, क्योंकि अुसकी कोअी राष्ट्रीय सरकार न थी। लेकिन स्टेटिस्टिकल अॅब्स्ट्रैक्ट (आँकड़ोंके .खुलासे) के मुताबिक, ३१ मार्च १९२६को हिन्दुस्तानका सरकारी ऋण १००० करोड़से ज्यादा था। अुसकी विगत यह है —

१. माअिन्यूट्स ऑफ अेविडेन्स ऑन दी अफेअर्स ऑफ दी औस्ट अिण्डिया कम्पनी, १८१३

हिन्दुस्तानमें :

| | | |
|---|---|---|
| क़र्ज़े | ३६८ ·२९ | |
| सरकारी हुण्डियाँ वग़ैरा | ४९ ·६५ | ४१७ ·९४ |
| प्रॉविडेण्ट फण्ड, पो० ऑ० सेविंग्स बैंक वग़ैरा | | ९४ ·५५ |

अिंग्लैण्डमें :

| | |
|---|---|
| १/२ फ़ी रुपयेके हिसाबसे | ५१३ ·२९ |
| | १०२५ ·७८ करोड़ रुपये |

हुण्डियों और रोज़मर्राके देनेको छोड़कर बाक़ी देनेके ये विभाग किये गये हैं :

| | |
|---|---|
| 'अुत्पादक' | ७३७ ·१८ |
| 'अनुत्पादक' | २२१ ·८८ |
| | ९५९ ·०६ करोड़ |

'अुत्पादक ऋण'का बँटवारा अिस तरह किया गया है :

| | |
|---|---|
| रेलवे | ६२६ ·०६ |
| आबपाशी | ९६ ·०४ |
| डाक तार | १३ ·०० |
| जंगलात, नमक वग़ैरा | २ ·०८ |
| | ७३७ ·१८ करोड़ |

अूपरके आँकड़ोंका अितना ही मतलब है कि अुस तारीख़ तक सरकारका ख़र्च आमदनीसे १००० करोड़ रुपये ज़्यादा था। अिससे ज़्यादा तफ़सील बिलकुल भरोसेके क़ाबिल नहीं है और ज़्यादातर बनावटी है, क्योंकि कोअी ख़ास क़र्ज़ किसी अुत्पादक या अनुत्पादक कामके लिअे या किसी ख़ास जायदादके बदलेमें नहीं लिये गये। किसी क़र्ज़को रेलवे या आबपाशीके लिअे अलग रख देना सम्भव नहीं। अिनका वर्गीकरण और वितरण दोनों मनमाने ढंगसे किये गये हैं। 'अनुत्पादक' ऋणोंको शायद आमदनीमेंसे घटा देनेकी सरकारी नीतिके कारण 'अुत्पादक' और 'अनुत्पादक' ऋणोंका शुरूका अनुपात भी हमेशा बदलता रहा है। यह

जनताकी आँखोंमें धूल झोंकनेकी अेक हिसाबी चाल थी, जिससे करदाता यह समझे कि ज़्यादातर ऋणकी क़ीमतकी जायदाद मौजूद है। अगर अिन ऋणोंकी जाँच की जाय, तो पहली ज़रूरत तो यह है कि अिस दिखावटको दूर किया जाय और याद रखा जाय कि कुल 'सरकारी ऋण' सिर्फ़ सरकारका आमदनीसे ज़्यादा किया गया खर्च है, या जैसे जैसे घाटा होता गया, अुधार ले लेकर अुसे पूरा किया जाता रहा। जब यह सफ़ाअी हो जायगी, तब जाँच पड़तालका विषय अितना ही रह जायगा कि किन किन मदोंमें यह ज़्यादा खर्च किया गया। जैसा हम पहले ही समझा चुके हैं, ये मदें अिन दोमेंसे अेक किस्मकी हो सकती हैं :

१. खास ज़रूरतके वक़्त किया हुआ खर्च

२. पूँजी लगानेमें हुआ खर्च

अगर ये खर्चे लोगोंकी तरफ़से और हिन्दुस्तानकी भलाअीके लिअे किये गये होते, तो ज़रूर अुनकी ज़िम्मेदारी हमारी होती। लेकिन अगर हमें यह पता लगे कि हमारे हिसाबमें वे रक़में भी हमारे नामें लिखी गअी हैं जो वाजिब नहीं हैं, तो अिन रक़मोंको नामंज़ूर करना पड़ेगा। ये नामंज़ूर की हुअी रक़में अूपर दिये हुअे सरकारी ऋणके आँकड़ेके बराबर होंगी, अगर ऋण पूरा ही अिन मदोंके कारण हो; वे रक़में ऋणोंसे कम होंगी, अगर खास मौक़ेपर किया गया खर्च या पूँजी लगानेका खर्च कुछ कुछ सरकारी आमदनीमेंसे किया गया हो और पूरी तरह क़र्ज़ लेकर ही न किया गया हो; और वे रक़में ऋणसे ज़्यादा होंगी, अगर सरकारी ऋण समय समयपर ज़ायद आमदनीमेंसे घटाया गया हो। सच बात यह है कि हिन्दुस्तानमें तो यह पिछली बात ही हुअी है। ज़ायद आमदनीमेंसे बड़ी बड़ी रक़में अिन ऋणोंको, खास तौरपर अनुत्पादक ऋणोंको, घटानेके लिअे अिस्तेमाल की गअी हैं। जिस आर्थिक लेन-देनके बारेमें शंका हो, अुस सारेका ठीक ठीक हिसाब तैयार किया जाय, तो अिन मदोंका जोड़ १००० करोड़के सरकारी ऋणके आँकड़ेसे बढ़ जायगा। रक़में कुछ भी हों, नतीजा यही निकल सकता है कि ये रक़में हिन्दुस्तानके हिसाबसे निकाल दी जानी चाहियें और जिन लोगोंके नामें लिखना वाजिब है, अुनके नामें लिखी जानी चाहियें।

अिस ज़मानेमें जिन मदोंका खर्च हिन्दुस्तानके नामें डाला गया है, अुनका हम नीचे विचार करेंगे :

| | लाख पौण्ड |
|---|---|
| १. पहला अफ़ग़ान युद्ध | १२० |
| २. बर्माकी दो लड़ाअियाँ | १४० |
| ३. चीन, औरान वग़ैराकी चढ़ाअियाँ | ६० |
| ४. हिन्दुस्तानका 'ग़दर' | ४०० |
| ५. कम्पनीकी पूँजी और मुनाफ़ेका भुगतान | ३७० |
| | १०९० लाख पौण्ड |

## अफ़ग़ान युद्ध

यह लड़ाअी ग्रेट ब्रिटेनकी सरकारने अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी अिच्छाके खिलाफ़ मोल ली थी। फिर भी अिसका सारा खर्च हिन्दुस्तानके सिरपर थोपा गया है। अिस बारेमें सर जार्ज विंगेटने लिखा है :

"अिनमेंसे अफ़ग़ान युद्ध बहुत ध्यान देने लायक़ है और अब यह अच्छी तरह समझ लिया गया है कि यह लड़ाअी ब्रिटिश सरकारने कोर्ट ऑफ़ डाअिरेक्टर्सकी सलाहके बिना और अुनके विचारोंके विरुद्ध मोल ली थी। सच पूछा जाय तो वह खालिस ब्रिटिश लड़ाअी थी। लेकिन अैसा होनेपर भी और कोर्ट ऑफ़ डाअिरेक्टर्सकी अेक होकर गम्भीर रायें जाहिर कर देनेके बावजूद और अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके मालिकोंकी सभाके अिस प्रस्तावके होते हुअे भी कि अिस लड़ाअीका सारा खर्च हिन्दुस्तानके खज़ानेपर ही न डाला जाय, मन्त्रि-मण्डलने अैसा ही कराया।"

अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके अध्यक्ष और अुपाध्यक्षने अपने ६ अप्रैल १८४२के पत्रमें अिसका विरोध करते हुअे लॉर्ड फ़िट्ज़जेरल्डको लिखा था :

"अिन हालातमें कोर्टका हिन्दुस्तानकी तरफ़से यह दावा करनेका फ़र्ज़ हो गया है कि अुसे अुस खर्चसे बचाया जाय, जो न्याय और

निष्पक्षतासे देखनेपर अुसपर डालना वाजिब न हो; और यहाँ कोर्ट यह नहीं चाहती कि वह सिन्धु नदीके पारकी मुहिमोंके मक़सदके बारेमें समयसे पहले कोअी सवाल अुठाये, फिर भी यह अर्ज़ करना पड़ता है कि किसी भी अिन्साफ़ या मसलेहतके खयालसे अिन फ़ौजी कार्रवाअियोंका और जो कुमुक भेजी जानेवाली है अुसका सारा भार हिन्दुस्तानके खज़ाने पर नहीं डाला जा सकता।"

२७ जून, १८४२को अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी जनरल कोर्टने यह निश्चय किया :

"पार्लियामेण्टके सामने पेश किये हुअे कागज़ातसे जैसा ज़ाहिर होता है, अफ़ग़ानिस्तानके मामलोंमें ब्रिटिश हस्तक्षेपसे सम्बन्ध रखनेवाले तमाम हालातपर विचार करनेपर अिस कोर्टकी राय है कि अिस लड़ाअीका सारा खर्च हिन्दुस्तानपर नहीं डाला जाना चाहिये, बल्कि अिसका अेक हिस्सा युनाअिटेड किंगडमके खज़ानेको बर्दाश्त करना चाहिये।"

अेशियाकी दूसरी लड़ाअियोंके बारेमें सर जार्ज विंगेटने लिखा था :

"हमारे साम्राज्यकी हदके बाहर हमने अेशियामें जितनी लड़ाअियाँ लड़ी हैं, वे भारत सरकारके सैनिक और आर्थिक साधनोंसे लड़ी हैं, यद्यपि अिनमेंसे कुछका हेतु बिलकुल अंग्रेज़ोंका अपना था और कुछका सम्बन्ध हिन्दुस्तानकी भलाअीसे बहुत दूरका था। अिन लड़ाअियोंका बीड़ा भारत सरकारने अुस वक़्तके ब्रिटिश मन्त्रियोंकी हिदायतोंके अनुसार अुठाया था और ये हिदायतें बोर्ड ऑफ कण्ट्रोलके अध्यक्षोंके मारफ़त मिलती थीं; और अुनका जो भी नतीजा हुआ है, अुसके लिअे अंग्रेज़ क़ौम साफ़ तौरपर ज़िम्मेदार है।"

## अीरानी युद्ध

अीरानकी लड़ाअीके बाबत अुनका कहना है :

"पिछले अीरानके जंगका अैलान ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डलने अेक अैसी नीतिके मातहत किया था, जिसके साथ हिन्दुस्तानका दरअसल कोअी वास्ता न था। फिर भी लड़ाअी हिन्दुस्तानके सिपाहियों और साधनोंसे लड़ी गअी और सच पूछा जाय तो अुसका आधा खर्च ही बादमें अिस देशने बर्दाश्त किया था। सच तो यह है कि हमारी सारी अेशियाअी

लड़ाअियोंमें आदमी और हर तरहके साधन हिन्दुस्तानसे लिये गये हैं और अिस तरह दी गअी मददकी पूरी क़ीमत अुसे कभी नहीं चुकाअी गअी। अिससे हमारी हिन्दुस्तान सम्बन्धी नीतिके अिकतरफ़ा और स्वार्थी होनेका अकाटय प्रमाण मिलता है।"[1]

**"ग़दर"**

मार्च, १८५९में अीस्ट अिण्डिया क़र्ज़ेपर बोलते हुअे जॉन ब्राअिटने कहा था :

"मेरे खयालसे विद्रोहका जो ४ करोड़ पौण्ड खर्च हुआ है, अुसका बोझा हिन्दुस्तानपर डालना बड़ी बुरी बात होगी। यह सब पार्लियामेण्ट और अिंग्लैण्डके लोगोंकी बदअिन्तज़ामीका नतीजा है। अगर न्याय ही करना हो, तो बेशक ये चार करोड़ पौण्ड अिस मुल्ककी जनतासे वसूल किये गये करसे दिये जाने चाहियें।"

सर जार्ज विंगेटने "हिन्दुस्तान सम्बन्धी नीतिकी बेमिसाल नीचता और स्वार्थी परम्परा" की तरफ़ अिन शब्दोंमें ध्यान दिलाया है :

"तो हिन्दुस्तानके ग़दरका अितना संकट होनेपर भी और हिन्दुस्तानके खज़ानेकी बुरी हालत हो जानेपर भी ग्रेट ब्रिटेनने हिन्दुस्तानसे न सिर्फ़ वहाँ भेजी गअी फ़ालतू पल्टनोंका यहाँसे रवाना होनेके बादसे सारा खर्च वसूल किया है, बल्कि अिस मुल्कसे रवाना होनेके पहलेके छः महीनोंका भी अुन पल्टनोंका खर्च तलब किया है। अैसा करनेके लिअे कारण हो सकते हैं, लेकिन अिससे ब्रीनसकी याद आती है। अुसने तराज़ूमें अपनी तलवार डालकर कहा था कि हारे हुअे रोमन लोग अुसके बराबर हर्जानेकी रकम दें; लेकिन चूँकि सिपाहियोंसे काम हमने लिया था और अुनकी तनख्वाहका खर्च अुस समयके लिअे अिस राज्यके अुद्योगपति-वर्गकी हिमायतमें हुआ था और अुससे हिन्दुस्तानका कोअी फ़ायदा नहीं हो सकता था, अिसलिअे हमारा नैतिक फ़र्ज़ है कि हम न्याय या अीमानदारीके वे अुसूल समझायें, जिनके मातहत हमने भारतके बुरी तरह भारसे दबे हुअे खज़ानेपर यह भारी खर्च और डाल दिया है।"[2]

---

१. अवर फ़ाअिनेन्शियल रिलेशन्स विथ अिण्डिया, पृ० १७-१९

२. ,, ,, पृ० १५-१६

जंगी दफ्तरने १४ अप्रैल, १८७२के अेक पत्रमें जो 'असाधारण प्रार्थना' की थी, अुसके बाबत भारतमन्त्रीने ८ अगस्त, १८७२को यह लिखा :

"लेकिन यह याद रखना चाहिये कि अगर सम्राटके राजके किसी और हिस्सेमें अिस तरहकी लड़ाअीकी कार्रवाअी आवश्यक हुअी होती, तो वह कार्रवाअी साम्राज्य सरकारको ही करनी पड़ती और अुसका ज़्यादातर बोझ अुसीको अुठाना पड़ा होता; लेकिन हिन्दुस्तानके ग़दरकी बात यह है कि अुसे दबानेके ख़र्चेका कोअी हिस्सा साम्राज्यके ख़ज़ानेपर नहीं पड़ने दिया गया और यह सारा ख़र्च हिन्दुस्तानी करदाताओंने दिया या वे अब दे रहे हैं।"

## अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी पूँजी और अुसका मुनाफ़ा

हमारी सूचीमें हमने जो मद आख़िरमें दिखाअी है, वह अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी पूँजीकी ख़रीदका मूल्य और अुसपर दिया हुआ ब्याज है। यह बहुत ही अजीब आर्थिक सौदा है। अेक कम्पनीके हक़ कोअी ख़रीद लेता है, लेकिन ख़रीदके दाम ख़रीददार न देकर, ख़ुद कम्पनी ही ब्याज समेत देती है! अैसी दूसरी मिसाल अिस सट्टेबाज़ कम्पनीकी व्यवस्थाके गन्दे अितिहासमें भी मिलनी मुश्किल है।

जो चन्द मदें अूपर बयान की गअी हैं, जिनका कुल जोड़ १०९.० लाख पौण्ड होता है और जो ब्रिटिश ताज़ने हिन्दुस्तानकी पूरी ज़िम्मेदारी सँभाली अुससे पहलेकी हैं, वे साफ़ तौरपर ब्रिटिश ख़ज़ानेपर पड़नी चाहिये थीं; मगर बेजा तौरपर और बेअीमानीसे बावजूद बार बार विरोध होनेके भी डाल दी गअीं हिन्दुस्तानके ख़ज़ाने पर।

## ताज़की मातहतीमें

'ग़दर'के बाद ब्रिटिश ताज़ने हिन्दुस्तानकी हुकूमतकी बागडोर सँभाली। अिससे झूठे जमाख़र्चेकी नीतिको चलाना बहुत ही आसान हो गया। अब कोर्ट आफ़ डाअिरेक्टर्सको राज़ी रखने या अुनके विरोधका सामना करनेकी झंझट भी नहीं रही। अब अितनी ही ज़रूरत रह गअी कि ब्रिटिश ख़ज़ानेका कुछ करोड़का भार हलका करना हुआ, तो अनचाहे ख़र्चेको हिन्दुस्तानके ख़ज़ानेके नाम लिख देनेका फ़रमान हिन्दुस्तानकी सरकारके नाम भेज दिया और भारत सरकार अूपरसे आनेवाले

अिन आदेशोंको .खुशीसे मान लेती थी। बेशक लॉर्ड नार्थब्रूक-जैसे कुछ सिरफिरे अफ़सर भी थे, जो बेवकूफ़ीसे मन्त्रि-मण्डलके वज़ीरोंकी धर्मात्मापनकी बातोंपर भरोसा करते थे और साम्राज्यवादी कामोंमें न्याय और अीमानदारीके सिद्धान्तोंको लागू करनेके अपने ग़लत ख़यालोंमें आकर बेअीमानियोंसे नाराज़ होकर अपने पदोंसे अिस्तीफ़ा दे देते थे। अिस तरह फ़ालतू मालको समुद्रमें फेंकते और समुद्रपर तैरते हुअे मालको बटोरते हुअे साम्राज्य सरकारका जहाज़ अचल और निर्दय होकर चलता रहा।

अिस तरहके जमाखर्चके कुछ अुदाहरणोंकी जाँच पड़ताल कर लें।

## (क) बाहरी लड़ाअियाँ

जहाँ तक बाहरी लड़ाअियोंके अुस खर्चका सम्बन्ध है, जो अन्यायसे हमपर लाद दिया गया, नीचे लिखे खर्च खासतौर पर ध्यान देने लायक़ हैं:

| | | |
|---|---|---|
| १८६७ अबीसिनियाकी लड़ाअी | ६००,००० | पौण्ड |
| १८७५ पीराककी मुहिम | ४१,००० | ,, |
| १८७८ दूसरा अफ़ग़ान युद्ध | १७,५००,००० | ,, |
| १८८२ मिस्र | १,२००,००० | ,, |
| १८८२ सरहदकी लड़ाअियाँ | १३,०००,००० | ,, |
| १८८६ बर्माकी लड़ाअी | ४,७००,००० | ,, |
| १८९६ सूकिम | २००,००० | ,, |
| | लगभग ३८ | करोड़ रुपये |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १९१४–१९ यूरोपकी लड़ाअीका खर्च | ३९ | करोड़ | रुपये |
| ,, ,, ,, 'दान' | १५० | ,, | ,, |
| रक्षापर ज्यादा खर्च | १७०·७ | ,, | ,, |
| | ३९७·७ | करोड़ | रुपये |

अबीसिनियाकी लड़ाअीके बारेमें, फ़ॉसेट कमेटी (१८७६) के सामने गवाही देते हुअे सर चार्ल्स ट्रेवेलियनने कहा था:

"अबीसिनियाकी लड़ाअीका कारण हमारे सारे ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाली साम्राज्यशाहीकी भावना थी और अुसका वास्ता जितना

हमारे यूरोप और अमरीकाके सम्बन्धोंसे था, अुतना हिन्दुस्तानके सम्बन्धोंसे नहीं था। . . . .

"सच तो यह है कि हिन्दुस्तानके लोगोंको अबीसिनियाके बारेमें कुछ भी मालूम न था।"

अिसके बाद अुन्होंने १६००वें सवालके जवाबमें कहा था :

"सच पूछा जाय तो अबीसिनियाकी हमारी मुहिमोंसे ऑस्ट्रेलिया और कनाड़ाका जितना वास्ता था, अुससे ज्यादा वास्ता हिन्दुस्तानका किसी भी तरह नहीं था और अगर हमने अुस लड़ाअीके खर्चेमें मदद करनेकी माँग ऑस्ट्रेलिया और कनाड़ासे नहीं की, तो अुसका अेक मात्र कारण यह था कि हम अच्छी तरह जानते थे कि वे ़गुस्से और तिरस्कारसे अैसे प्रस्तावको ठुकरा देंगे, वे अुसपर ज़रा भी ध्यान नहीं देंगे। क्या वे ध्यान देंगे? ख़ैर, अेक अीमानदार आदमीकी हैसियतसे यह कहना मेरा धर्म है कि मुझे कोअी सच्चा फ़र्क़ नहीं दिखाअी देता। जिन कार्रवाअियोंसे अबीसिनियाकी लड़ाअी पैदा हुअी, अुनसे हिन्दुस्तानका कोअी सम्बन्ध नहीं था और न अुसके नतीजेसे ही अुसका बहुत वास्ता था।"[1]

अर्ल आफ़ नार्थब्रूकने वेल्बी कमीशन (१८९७) के सामने बयान दिया था कि अबीसिनियाकी लड़ाअीका खर्च अेक अैसी रक़म है, जिसका दावा करनेके लिअे हिन्दुस्तानके पास न्याय और अीमानदारी दोनोंके खयालसे कारण हैं।"[2]

अिसके अलावा पीराककी मुहिमके बारेमें जो रक़म ग़ैरक़ानूनी ढंगसे हिन्दुस्तानपर डाली गअी, अुसपर लॉर्ड नार्थब्रूकने नीचे लिखी शहादत की थी :

"मैं अुस वक़्त गवर्नर जनरल था और मैंने यह खर्च हिन्दुस्तानसे वसूल करनेका विरोध किया था। लेकिन भारत सरकारकी नाराज़ीपर कोअी ध्यान नहीं दिया गया। अितना ही नहीं, क़ानूनसे पार्लियामेण्टकी दोनों सभाओंमें जो चर्चा होनी चाहिये थी, वह भी नहीं हुअी। अिस

---

१. पार्लियामेण्टरी कमिटी ऑन अीस्ट अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर, १८७६, जिल्द ३, पृष्ठ १५१

२. अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर कमीशन, जिल्द ३, पृष्ठ २३

तरह क़ानून तोड़ा गया और हिन्दुस्तानपर अिस तरह जो ख़र्च डाल दिया गया, वह कभी नहीं लौटाया गया। वह ख़र्च अुस वक़्तसे क़ानूनके ख़िलाफ़ और भारत सरकारके विरोधके बावजूद हिन्दुस्तानके ही जिम्मे रहा है।"[1]

दूसरे अफ़ग़ान युद्धपर पार्लियामेण्टकी चर्चाके दरमियान अपने भाषणमें मि० फ़ॉसेटने अुस लड़ाअीका ख़र्च हिन्दुस्तानपर डाले जानेका विरोध किया और कहा था :

"हिन्दुस्तानमें अेक अैसी लड़ाअी हुअी, जिसके लिअे हिन्दुस्तानके लोग ज़िम्मेदार नहीं थे और जो हमारी ही अपनी यूरोपकी नीति और कामोंसे पैदा हुअी थी। लेकिन हम अुसका पाअी-पाअी ख़र्च हिन्दु-स्तानियोंसे वसूल करनेवाले हैं, हालाँ कि न अुन्हें स्वराज हासिल है और न अुनका कोअी प्रतिनिधित्व है।"[2]

और मि० ग्लैडस्टनने मि० फ़ासेटकी हिमायत की और कहा था :

"अिस अफ़ग़ान युद्धको साफ़ तौरपर साम्राज्यवादी ढंगकी लड़ाअी मान लिया गया है . . . लेकिन मेरे ख़यालसे (५० लाख पौण्डकी) छोटीसी रक़म ही नहीं, बल्कि जिसे मेरे माननीय मित्र, अर्थ-मन्त्री, ख़ासी और बड़ी रक़म कहेंगे, कमसे कम वह अिस देशको भुगतनी चाहिये।"[3]

अिस लड़ाअीके बाद अमीरको १८९४ तक ६ लाख सालाना दिया जाता रहा। अुसके बाद अुन्हें १२ लाख सालाना दिया गया। लड़ाअीके ख़र्चके अलावा ये रक़में भी हिन्दुस्तानके ख़ज़ानेसे दी गअी थीं।

१८८२ की मिस्रकी फ़ौजी कार्रवाअीपर वेल्बी कमीशनके सामने गवाही देते हुअे भारत सरकारके फ़ौजी मन्त्री, मेजर जनरल अी० अेच० अेच० कोलनने अपनी यह राय दी थी कि "अिस क़िस्मकी मुहिमके लिअे हिन्दुस्तानपर अेक कौड़ीका भी ख़र्च नहीं पड़ना चाहिये था।"

सरहदी लड़ाअियोंके बारेमें हिन्दुस्तानके सरकारी ख़र्चेकी जाँच करनेवाले कमीशनने कहा है, "ये सब लड़ाअियाँ जहाँ तक कि बड़े साम्राज्यके

---

१. अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर कमीशन, १८९५, जिल्द ३, पृष्ठ २०
२. हंसार्ड, जिल्द २५१, पृ० ९२६
३. ,, ,, २५१, पृ० ९३५

सवालकी अंग हैं, वहाँ तक अुनका खर्च खास तौरपर साम्राज्यके खज़ानेको ही करना चाहिये था।"[1]

बर्माकी लड़ाअीका खर्च हिन्दुस्तानपर डालना कहाँ तक ठीक था, अिस बारेमें मिस्टर डी० अी० वाचाने (बादमें वे सर दिनशा हो गये) वेल्बी कमीशनके सामने बयान किया :

"जहाँ तक अूपरी बर्माका ताल्लुक़ है, फ़ौजी चढ़ाअीका सारा खर्च और बादकी हुकूमतकी लागत सारीकी सारी अिंग्लैण्डसे हिन्दुस्तानको मिलनी चाहिये और अुस प्रान्तको, जैसा कांग्रेसने सुझाया था, हिन्दुस्तानसे अलग करके अुसे सम्राट्का सीधा अिलाका बना देना चाहिये। बर्मापर रंगून और मॉंडलेके अंग्रेज़ व्यापारियोंके कहनेसे क़ब्ज़ा किया गया था। हिन्दुस्तानने कभी अुसे मिलानेकी माँग नहीं की थी और यह हिन्दुस्तानके साथ अन्याय है कि अंग्रेज़ पूँजीपतियोंकी भलाअीके लिअे और ब्रिटिश साम्राज्यके फैलावकी खातिर हिन्दुस्तानके खजानेसे कोअी खर्च दिया जाय।"[2]

और मि० गोखलेने अुसी कमीशनसे कहा था :

"बर्माको साम्राज्यवादी नीतिके अनुसार और साम्राज्यके व्यापारिक हितमें फ़तह किया गया था और अुसमें हिन्दुस्तानकी किसी खास भलाअीका खयाल नहीं था।"[3]

सूकिमकी चढ़ाअीका खर्च भारत सरकारके विरोध करनेपर भी हिन्दुस्तानके मत्थे मढ़ दिया गया। भारत सरकारने लिखा था :

"सूकिमकी स्थिति मज़बूत करने और मिस्री फ़ौजको नील नदीके किनारेपर अिस्तेमाल करनेके लिअे आज़ाद करनेके खातिर हमसे कहा गया है कि हिन्दुस्तानकी देशी सेनाके आदमी रक्षाका काम करनेके लिअे दिये जायँ। लेकिन अूपर बताअी हुअी नीतिपर अमल करनेमें हमें हिन्दुस्तानका कोअी दूरका भला भी नहीं दीखता। यह तो कहा नहीं जा सकता कि स्वेज़ नहरकी सलामतीका सवाल है और हिन्दुस्तानके करदाता,

---

१. अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर, जिल्द ४, पृ० १८७

२. अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर कमीशन, जिल्द ३, पृ० २०४

३. ,, ,, ,, पृ. २४३

जिन्हें सूकिम जानेवाली फ़ौजका खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है, अिस फ़ौजके लिअे अुनपर लगाये जानेवाले टैक्सके कारणोंको मुश्किलसे ही समझ सकेंगे, क्योंकि यह सेना हिन्दुस्तानमें काम न करके मिश्रकी सरहदपर व्यवस्था क़ायम रखनेके, मिश्रके अेक प्रान्तके कुछ हिस्सेको फिरसे फ़तह करनेके या अिटलीकी सेनाको मदद पहुँचानेके लिअे अिस्तेमाल होगी । . . . अैसे हालातमें हमें जिस देशका राजकाज सौंपा गया है अुसके हितमें हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि अेक बार निहायत ज़ोरदार शब्दोंमें अुस नीतिका विरोध करें, जिससे हिन्दुस्तानके खजानेपर अुन कामोंका खर्च डाला जा रहा हो, जिसमें हिन्दुस्तानका कुछ भी भला न हो । यह नीति हिन्दुस्तानके साथ अन्याय करती है; क्योंकि अिससे अिंग्लैण्डको अुधार दी हुअी फ़ौजका खर्च हिन्दुस्तानपर पड़ता है और यह अुसूल अुस अुसूलसे भिन्न है जो अिंग्लैण्ड हिन्दुस्तानको अंग्रेजी फ़ौज अुधार देते वक़्त लागू करता है । यह नीति मसलेहतके हिसाबसे भी अच्छी नहीं है; क्योंकि अिससे हमारी सरकारपर अैसे हमले हो सकते हैं, जिनका कोअी माक़ूल जवाब नहीं है ।"[१]

## फुटकर ख़र्च

अिन बाहरी लड़ाअियोंके खर्चके अलावा, हिन्दुस्तानके ख़ज़ानेपर दुनिया भरके दूसरे खर्चोंका बोझा भी डाल दिया गया है, जैसे अीरानी मिशन, चीनी कॉन्सल और राजदूतावासके खर्च वग़ैरा । अिस मामलेमें भी मि. रैम्ज़े मेकडोनल्डका हवाला देना मुनासिब होगा :

"ग़ैर फ़ौजी पहलूको देखें तो वहाँ भी कअी खर्च अितने आपत्तिजनक हैं कि अुनका अन्दाज़ ख़र्चकी रक़मोंसे ही नहीं लगाया जा सकता । भारत-मन्त्रिके दफ़्तरका ख़र्च हिन्दुस्तानके ख़ज़ानेसे दिया जाता है । मगर अिस तरह अुपनिवेशोंके दफ़्तरका खर्च अुपनिवेशोंसे नहीं लिया जाता । सम्राट और भारत-मन्त्रि हिन्दुस्तान जाते हैं तो अुनकी यात्राओंका खर्च भी हिन्दुस्तानके करदाता देते हैं । ये रक़में जो अिस वक़्त लगभग ४ लाख पौण्ड हैं, बराबर बढ़ती जा रही हैं । ये सब साम्राज्यके खर्चे

१. फायनैन्शियल डेवलमेण्ट्स अिन मॉडर्न अिण्डियासे अुद्धृत, पृ० १३१

हैं और ज़्यादातर भारत सरकारसे अलग हैं । अुनको हिन्दुस्तानके बजटमें दिखाना नीचता है और हमारी शानके बिल्कुल खिलाफ़ है ।" [१]

कम्पनीके डाअिरेक्टरोंने जो बुरेसे बुरे तरीक़े काममें लिये वैसे ही तरीक़ोंकी मिसालें ब्रिटिश सरकारके अर्थ-विभागवालोंके व्यवहारमें पाअी जाती हैं । रेड सी अैण्ड अिण्डियन टेलीग्राफ़ कम्पनीके मामलेका अुदाहरण ही अेक लीजिये; यह १८५८में बनी थी और अर्थ-विभागने अुसे पचास सालके लिअे ४½% की गारण्टी दी थी । अेक दो दिनके बाद तारकी लाअिन टूट गअी और सालाना रक़मका आधा हिस्सा हिन्दुस्तानी खज़ानेपर डाल दिया गया । अिस मामलेमें वेल्बी कमीशन कहता है :

"१८६१में अेक क़ानून पास किया गया कि गारण्टीकी अब यह शर्त रहेगी कि तार ठीक तरह काम देता हो । १८६२में दूसरा क़ानून बनाया गया कि लाअिन खबरें नहीं पहुँचा रही है, अिसलिअे सम्पत्ति दूसरी कम्पनीके सुपुर्द कर दी गअी और पुरानी कम्पनीकी गारण्टी बदलकर ४६ सालके लिअे ३६००० पौण्ड सालाना रक़म कर दी गअी । यह शर्त भी रख दी गअी कि सालाना रक़मकी आधी यानी १८०२७ पौण्ड प्रबन्ध खर्चके रूपमें ४ अगस्त १९०८ तक हिन्दुस्तान सम्राटके खज़ानेको देता रहे ।" [२]

अिस व्यवस्थाके अनुसार जो रक़म दी गअी, वह ४ फ़ी सदी ब्याजके हिसाबसे वापस माँगी जाय, तो कुल रुपया २० लाख पौण्डके आसपास पहुँचेगा ।

## सालाना फ़ौजी ख़र्च

यह बुरी बात सबको मालूम है कि हमारी सरकारी आमदनीका ज़्यादातर रुपया सरकारके बुनियादी कामोंपर खर्च कर दिया जाता है । राष्ट्र-निर्माणके कामोंपर खर्च न करके फ़ौजी खर्चके साधन जुटानेसे देशकी कितनी हानि हुअी है, अिसकी तफ़सीलमें जानेकी यह जगह नहीं है । लेकिन यह ध्यान देनेकी बात है कि सन् १८५७से भारतमें सेना अेक तरहसे क़ब्ज़ा रखनेवाली फ़ौजका ही काम करती है । अुस तारीख

१. गवर्नमेण्ट ऑफ़ अिण्डिया, पृष्ठ, १५५

२. अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर कमीशन, १८९५, जिल्द २, पृष्ठ ३७०

तक गोरे सिपाहियोंसे हिन्दुस्तानी सिपाही पचगुने होते थे। अुसके बादसे अनुपात दुगुना ही कर दिया गया, ताकि अंग्रेज़ोंका क़ब्ज़ा सही-सलामत रहे। हिन्दुस्तानी फ़ौजकी ताक़त साम्राज्यवादी कामोंके लिअे पूरी क़ायम रखी गअी है, यह अिस बातसे ज़ाहिर है कि जब कभी हिन्दुस्तानसे बाहर साम्राज्यवादी लड़ाअियोंके लिअे हिन्दुस्तानी सिपाहियोंकी ज़रूरत हुअी अुन्हें बग़ैर किसी हिचकिचाहटके बाहर भेज दिया गया और अिस बातकी कोअी कोशिश नहीं की गअी कि अुनकी ग़ैर मौजूदगीमें दूसरे सिपाही हिन्दुस्तानमें रख दिये जायँ। अिस तरहसे भारतका अंग्रेज़ोंके साम्राज्यवादी कामोंके लिअे फ़ौज मुहैया करनेकी 'पूर्वी समुद्रोंमें अेक छावनीके रूपमें' अिस्तेमाल किया गया है। चूँकि हर गोरे सिपाहीका ख़र्च हिन्दुस्तानी सिपाहीसे लगभग तिगुना-चौगुना माना जाता है, अिसलिअे भारत सरकारका फ़ौजी ख़र्च जितना होना चाहिये था, अुससे बहुत ज़्यादा रहा है। अगर सेना सिर्फ़ बचाव और भीतरी व्यवस्थाके लिअे ही रखी जाती और अुसमें हिन्दुस्तानी सिपाही होते, तो यह बात न होती। अैसी हालतमें मुनासिब यही है कि हिन्दुस्तानकी आवश्यकतासे अधिक जितना ख़र्च हुआ, वह ग्रेट ब्रटेनका बर्दाश्त करना चाहिये।

अिसके सिवा साम्राज्यके ख़यालसे फ़ौजको जिस अूँचे दर्जेपर सुसज्जित रखा गया है अुसकी ज़रूरत ख़ालिस स्थानीय कामोंके लिअे नहीं होती। वेल्बी कमीशनके अेक सदस्य मि० बुकाननने कमीशनकी रिपोर्टके अपने विशेष वक्तव्य नं० ४ में कहा है:

"यह पहले ही बता दिया गया है कि जहाँ तक देशके सैनिक बचावका सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान अुसका सारा ख़र्च देता है और यूनाअिटेड किंगडम कुछ भी नहीं देता। फिर भी हिन्दुस्तानके सैनिक बचावको क़ायम रखना साम्राज्यका अेक बड़ेसे बड़ा सवाल है।

"पूर्वमें हमारे साम्राज्यकी लड़ाअीमें मुख्य हाथ हिन्दुस्तानकी फ़ौजी ताक़तका रहा है। अुस ताक़तके कारण ही ग्रेट ब्रिटेन अेशियाकी अेक बड़ी सत्ता है। साम्राज्यके लिअे हिन्दुस्तानकी फ़ौजका कितना महत्त्व है, अिसका ज़बर्दस्त अमली सबूत वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता है, जो दक्षिण अफ़्रीकाकी लड़ाअीमें हमें हिन्दुस्तानसे मिल रही है। अेक

नाजुक घड़ीमें लगभग ६ हज़ार अंग्रेज़ सिपाही पूरी तरह लड़नेके लिअे तैयार हिन्दुस्तानसे नेटाल आनन फ़ाननमें भेज दिये गये, अुसके बाद और लोग चले गये और अिस वक़्त हिन्दुस्तानी पलटनें मॉरीशस, लंका, सिंगापुर और दूसरी जगहोंपर, जहाँसे ब्रिटिश सिपाही लड़ाअीके कामके लिअे हटा दिये गये हैं, रक्षाका काम कर रही हैं ।

"अिसलिअे अिसमें कोअी शक़ नहीं कि साधारण कारणोंसे और हमारे अिस ताज़ा अनुभवसे भी, कि हिन्दुस्तानकी सैनिक ताक़तसे साम्राज्यको कितनी बढ़िया मदद मिल सकती है, यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि हिन्दुस्तानकी ताक़त साम्राज्यकी ताक़त है और साम्राज्यके लिअे यह कर्त्तव्य पालन करके हिन्दुस्तानका यह दावा न्यायपूर्ण हो जाता है कि भारका कुछ हिस्सा साम्राज्यके खजानेको अुठाना चाहिये । अिस रकमका बन्दोबस्त किस तरह किया जाय, अिस बारेमें कठिनाअियाँ हो सकती हैं, पर अिसमें कोअी सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तानका दावा बिलकुल वाजिब है ।"[१]

१८८५–८६के आर्थिक ब्यौरेके १३६ वें पैरेमें अुस समयके अर्थ मंत्री सर ऑकलैण्ड कॉलविनने (लड़ाअियोंका खर्च छोड़कर) सेनाके खालिस खर्चका अन्दाज़ लगभग १५ करोड़ रुपये सालाना बताया था । अुन्होंने कहा था कि अिस रक़मको हिन्दुस्तान और अिंग्लैण्डका साधारण फ़ौजी खर्च समझा जा सकता है । अिससे किसी भी हिन्दुस्तानी सरकारको फ़ौजी खर्चका अेक अैसा पैमाना मिल जाता है, जिसे चीज़ोंके बदलते हुअे भावोंको देखते हुअे ठीक कर लिया जाय । अिस तरह कमीवेशी करनेपर सैनिक खर्चके लिअे नीचे लिखे माप क़ायम होते हैं :

| | |
|---|---|
| १८५९–६० से १८९९–१९०० | १५ करोड़ |
| १९००—१ से १९१४–१५ | २० करोड़ |
| अुसके बादसे | ३० करोड़ |

अिस हिसाबसे देखा जाय तो हिन्दुस्तानकी फ़ौजको साम्राज्यके कामोंके लिअे रखनेसे जो बहुत ज़्यादा सैनिक खर्च हुआ है और जिसे ग्रेट ब्रिटेनको बर्दाश्त करना चाहिये था, वह ६०० करोड़से कुछ अूपर होता

१. अिण्डियन अेक्स्पेण्डिचर कमिशन, १८९५, ज़िल्द ४, पृ. १४९

है। हिन्दुस्तानी करदाताके साथ अिन्साफ़ किया जाय, तो यह रक़म भी हिन्दुस्तानको वापस मिलनी चाहिये।

## झूठे ख़र्चेकी रक़मोंपर दिया गया ब्याज

कार-व्यवहारके सारे सिद्धान्तोंका तक़ाज़ा है कि जहाँ कोअी रक़म ग़लत नामपर लिखी गअी हो और अुस कर्ज़ेपर ब्याज दिया गया हो, तो अैसे ब्याजकी रक़म वापस मिलनी चाहिये। अगर हिन्दुस्तानका मूल ऋण ही ग़लत साबित हो जाय, तो यह माँग करना बिलकुल वाजिब है कि अुस ऋणके सम्बन्धमें दिया हुआ सब रुपया वापस किया जाय।

यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि ब्याजकी अिन रक़मों का जो दावा किया जाता है, वह किसी प्रासंगिक हानिके बदलेमें नहीं किया जाता, बल्कि जो नुक़सान सचमुच हुआ है, अुसका दावा किया जाता है। अैसी सूरतमें ब्याज .खुद मूलधन होता है। चूँकि वह ग़लतीसे दिया गया है, अिसलिअे अुसका दावा किया जाता है।

अगर शुरूमें ही ये रक़में ठीक ठिकानेपर नामें लिखी गअी होतीं, तो ब्याजकी रक़में अंग्रेज़ी खज़ानेपर पड़तीं। चूँकि अंग्रेज़ी खज़ानेको अुतनी राहत मिली थी, अिसलिअे अिस दावेका अितना ही मतलब है कि जिस पक्षको शुरूमें रुपया अदा करना चाहिये था वह अब चुका दे। बेपारी रिवाजको सख़्तीसे लागू किया जाय, तो अुसमें साधारण ब्याज देनेकी, ही गुँजायश नहीं है बल्कि अिस तरहकी रक़मोंपर भी ब्याज देनेकी यानी ब्याज दर ब्याज चुकानेकी भी गुँजायश है। लेकिन अभी तो दावा अितना ही है कि जो कुछ हिन्दुस्तानके कोषसे सचमुच निकाला जा चुका है, वह लौटा दिया जाय।

चूँकि ब्याजकी रकमें दर साल चुकाअी गअी हैं, अिसलिअे सत्तर सालसे ज़्यादा मियादमें मूल ऋण तिगुनेसे अधिक हो जाता है। लेकिन यह बसकी बात नहीं; क्योंकि मूल रक़में जो नामें लिखी गअी थीं, अुसका .खुद अंग्रेज़ोंने विरोध किया तब भी वे सालकी साल बराबर वसूल की जाती रही हैं।

सरकारी क़र्ज़ोंपर ब्याजकी दर समय समयपर ३½ से ७ फ़ी सदी तक रही है और यह तय करना कठिन है कि दावा किस दरका किया

जाय। तमाम सरकारी क़र्ज़ोंकी औसत दर ४% आती है और अिसलिअे यह अर्ज़ है कि अिन रक़मोंको ४% साधारण ब्याजके हिसाबसे ब्रिटेनसे वसूल करना बेजा नहीं माना जाना चाहिये। बाहरी लड़ाअियोंके खर्चे पर, औीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी पूँजी और ब्याजको बरी करनेके लिअे जो रक़म दी गअी अुसपर और 'लड़ाअीके दान' पर ब्याजका यह हिसाब लगाया जाय, तो वह ५७० करोड़ रुपयेसे ज़्यादा होता है। सन् १८६० से ब्याजके रूपमें कुल रक़म जो दी गअी है वह १२०० करोड़ रुपयेसे अधिक होती है। अिस तरह हमारे दावोंका मतलब यह होता है कि ब्रिटिश खज़ानेका भार हल्का करनेके लिअे हमारे कोषसे जितना रुपया दिया गया है, अुस सबका लगभग आधा हमें लौटाया जाय।

# ४

# मौजूदा ज़माना

## दानकी युक्ति

यहूदियोंकी पुरानी परम्परामें अेक अैसा रिवाज था कि अगर लड़का अपनी जायदादको 'कोर्बन' या दान बता देता, तो वह अुसे माँ-बापके काममें आनेसे बचा सकता था। अुस वक़्तसे लड़का माँ-बापके भरण-पोषणकी सारी ज़िम्मेदारीसे बच जाता था। यह कर्त्तव्यसे अेक तरहकी अपने आप ली हुअी मुक्ति है। अिसी क़िस्मकी कुछ तरकीबें ग्रेट ब्रटेनको भी निकालनी थीं, ताकि बीसवीं सदीके प्रकाशमें भण्डाफोड़ होनेसे बचा जा सके। पहले महायुद्धमें ग्रेट ब्रिटेनको हिन्दुस्तानमें बहुत भारी खर्चे करने पड़े, परन्तु ब्रटिश खज़ानेवाले अिस भारको अुठानेके लिअे तैयार नहीं थे। अिसलिअे अुन्होंने अपने दिल्लीके गुमाश्तोंको यह घोषणा करनेको कह दिया कि यह रक़म हिन्दुस्तानकी तरफ़से ग्रेट ब्रिटेनको दान की गअी है। अिस 'दान' कही जानेवाली चीज़का ग्रेट ब्रिटेन और हिन्दुस्तानके आर्थिक लेन-देनकी जाँच करनेवाली कांग्रेस सिलेक्ट कमेटीने विरोध किया है। अिस कमेटीमें बम्बअी सरकारके दो पिछले मशहूर

बड़े सरकारी वकील भी थे। अुनकी रायमें, जैसा अुनकी १९३१में प्रकाशित रिपोर्टसे ज़ाहिर है, भारत सरकार जिन क़ानूनोंके मातहत काम करती है अुनके अनुसार अुसे हिन्दुस्तानके खज़ानेसे ग्रेट ब्रिटेनको दान देनेका कोअी भी अधिकार नहीं था। अिसलिअे अिस तरहके दान ग़ैरक़ानूनी लेन-देन हुअे। लेकिन ग्रेट ब्रिटेनके जो जीमें आये अुसे करनेसे कौनसा क़ानून या हुक्म रोक सकता है? क्या वह दुनियाकी अेक अव्वल दर्जेकी ताक़त नहीं है, जो दुनियामें सलामती क़ायम रखती है और अणु बम बनानेवाले अमरीकाके साथ मिलकर चलती है? अिसलिअे बात यह है कि वह सभी क़ानूनोंसे परे हैं और अुसके हाथसे कोअी बुराअी हो नहीं सकती।

जो रक़में दरअसल दे दी गअी हैं और जिनके कुछ भाग हमारे नामे लिखे गये हैं, अुनके अलावा ग्रेट ब्रिटेनने जान बूझकर या अनजानमें दूसरे मामलोंमें भी अपने सिरपर क़र्ज़ कर लिया है। सरकारकी विनिमय-नीति और १९२०—२१के रिवर्स कौंन्सिल (अुल्टी हुण्डी)के व्यापारसे हिन्दुस्तानको बहुत भारी नुक़सान हुआ। अुस अेक सालमें ही यह नुक़सान २३½ करोड़का हुआ था।

विनिमयके सवालपर मि॰ मैक्डोनल्ड लिखते हैं:

"हिन्दुस्तानके खर्चेकी अेक और मद हिन्दुस्तानके लिअे अितनी बेजा है कि अुसकी तरफ़ ध्यान दिलानेकी ज़रूरत है। बहुत अर्से तक रुपयेका सोनेके साथ १ : १० का अनुपात था, यानी ग्रेट ब्रिटेनमें १८७३-४में रुपयेके बदलेमें २ शिलिंग मिलते थे। फिर वह गिरने लगा और अुसमेंसे २½ पेंस घट गये। धीरे धीरे वह बराबर घटता गया और अेक पेंसका फ़र्क़ भी हिन्दुस्तानके ऋणमें अेक करोड़ रुपया बढ़ा देता था; क्योंकि अुसे सोनेके आधारपर चुकाना पड़ता था। १८९५में वह गिरते गिरते १ शिलिंग १ पेंस रह गया; टकसालें बन्द कर दी गअीं और अैसी नीति शुरू हो गअी, जिससे रुपया प्रतीक बन गया और अुसकी रिवाजी क़ीमत १ शिलिंग ४ पेंस हो गअी। जिन अफ़सरोंको घरपर रुपया भेजना पड़ता था, अुन्हें बुरी तरह नुक़सान हुआ। १८९३से ज़्यादातर यूरोपियनोंके वेतन बढ़ा दिये गये और अुसे विनिमयकी क्षतिपूर्तिका भत्ता कहा गया।

१९१२में रुपयेकी क़ीमत तय हो जानेके कारण सरकारने अेक फ़ैसला जारी करके अिस विनिमय भत्तेके यूरोपियनोंकी तनख़्वाहें बढ़ा दीं, यह भी हिन्दुस्तानी करदाताके साथ अन्याय है । बेशक, अफ़सरोंको नुक़सान न होना चाहिये, लेकिन विनिमयके कारण अुनके वेतनपर असर पड़े, तो यह हिन्दुस्तानके सोचनेकी बात हरगिज़ नहीं है, साम्राज्यके सोचनेकी है। और ये फ़ालतू भत्ते ब्रिटिश खज़ानेसे मिलने चाहियें ।

"असलमें यह सवाल अिससे ज़्यादा व्यापक है । जब हिन्दुस्तानके विनिमयमें अितनी ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, तब गड़बड़ तमाम चाँदीके सिक्केवाले देशोंमें बराबर हुअी । लेकिन हिन्दुस्तानकी गड़बड़की बहुत कुछ ज़िम्मेदारी ब्रिटेनकी भारतीय नीतिपर है और ग्रेट ब्रिटेन पर हिन्दुस्तानके निर्भर रहनेसे यह मुश्किल बहुत बढ़ गअी ।

"विनिमयका विवाद लम्बा-चौड़ा और पेचीदा है, और कअी बातोंमें साफ़ भी नहीं है, लेकिन चूँकि रुपयेकी समस्याको बहुत नाज़ुक बना देनेवाली नीतिकी ज़िम्मेदारी अिस देशपर है, अिसलिअे रुपयेकी क़ीमतकी कमीका सारा ख़र्च अुसे हिन्दुस्तानपर ही नहीं डाल देना चाहिये था और जो ख़र्च लन्दन-सरकारको और अुसके अपने नौकरोंको हिन्दुस्तानमें रुपया देनेमें हुआ, वह तो हिन्दुस्तानके सिरपर पड़ना ही न चाहिये था।"[१]

फुटकर खर्चके अिस मदमें सौ करोड़से ज़्यादाका दावा होगा ।

## दुरुपयोग

**चूसना:** अिन आर्थिक सम्बन्धोंके सिवाय, ग्रेट ब्रिटेन समझता तो अपनेको हिन्दुस्तानका संरक्षक है, मगर अुसकी कोशिश यह रही है कि धरोहरको अपने ही काममें ले । साम्राज्य सरकारके गुमाश्ते हिन्दुस्तानमें आअी० सी० अेस० और आअी० पी० अेस० के लोग रहे हैं । अुन्हें जो वेतन मिलता रहा है, वह क्लाअिवके ज़मानेके डाकुओंकी लूटके बराबर ही है । हमारे देशके लोगोंकी आमदनीके साथ अिन भारी तनखाहोंका कोअी मेल नहीं बैठता; लेकिन अिस वक़्त जब राष्ट्रीय सरकार आ रही है, ब्रिटिश साम्राज्यवादके ये गुर्गे घबरा रहे हैं और भारतकी राष्ट्रीय हुकूमतकी नौकरी करनेको रज़ामन्द नहीं होते ।

---

१. गवर्नमेण्ट ऑफ अिण्डिया, पृष्ठ १५५

व्हाअिट हॉलमें बैठनेवाले अिनके मालिक अिन्हें साम्राज्यवादी ग्रेट ब्रिटेनकी कृपासे हाथ धो बैठनेका हर्जाना देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये अपनी परम्पराके अनुसार जो हर्जाना तय हो, अुसे .खुद बर्दाश्त न करके हिन्दुस्तानसे दिलवानेकी कोशिशमें हैं।

पिछली लड़ाअी अैसी थी जिससे हिन्दुस्तान अलग रहना चाहता था, फिर भी हमारे लाखों आदमियोंको बहकाकर ब्रिटिश झण्डेके नीचे लड़नेको ले जाया गया। अब ये लोग सेनासे अलग किये जा रहे हैं। अिन्हें पुरस्कार कौन दे, ग्रेट ब्रिटेन या हिन्दुस्तान? लेकिन हिन्दुस्तान अपने ज़बर्दस्त 'संरक्षक'के आगे लाचार है और अिसलिअे ग्रेट ब्रिटेनकी सेवाके बदलेमें अुन्हें हिन्दुस्तानकी ज़मीनें दी जा रही हैं। आश्चर्य यही है कि हिन्दुस्तानकी ज़मीनके जिन छोटे छोटे टुकड़ोंपर अितनी भीड़ है अुनके बजाय आस्ट्रेलिया और कनाड़ाकी लम्बी-चौड़ी ज़मीनें अिनाममें क्यों नहीं दी जातीं?

## ५

# गिरवी रखकर क़र्ज़ देनेका ज़माना

### काग़ज़ी क़र्ज़

पिछले अध्यायोंमें हमने देख लिया कि ग्रेट ब्रिटेनको ज़रूरत होनेपर अुसने हिन्दुस्तानके मत्थे मढ़कर रुपया वसूल करनेके लिअे क्या क्या तरकीबें की हैं। अिस परम्पराको साम्राज्यका निर्माण करनेवाले क्लाअिवने शुरू किया था। लेकिन अुसकी बेहया लूटमें कमसे कम अितनी तारीफ़की बात अवश्य थी कि वह खुली थी और कोअी बात छिपानेकी कोशिश नहीं की जाती थी। अुसके बादके लोगोंने जो तरीक़े अपनाये अुनमें लेन-देनके असली हेतुको छिपानेकी अेकसे अेक बढ़कर कोशिश की गअी। अीस्ट अिण्डिया कम्पनी भी क्लाअिवके बनाये हुअे रास्तेपर ही चली, लेकिन अुसने हिन्दुस्तानकी दौलतको ग्रेट ब्रिटेन पहुँचा देनेका अेक ज़्यादा आसान, मगर पोशीदा अुपाय काममें लिया। वह हिन्दुस्तानके ख़ज़ानेसे

रुपया लेकर अुससे यहाँ माल खरीदती और ग्रेट ब्रिटेनमें बिक्रीके लिअे भेज देती। अिस तरीक़ेमें ब्रिटिश खज़ानेवालोंने यह सुधार किया कि हिसाबकी बारीक चालबाज़ियोंसे वे तरह तरहके खर्चे हिन्दुस्तानके नामें लिख दिये गये जो साम्राज्यवादकी लड़ाअियोंपर हुअे थे और क़ानूनसे ग्रेट ब्रिटेनपर पड़ने चाहिये थे। मामूली आदमीके लिअे आँकड़ोंकी भूलभुलैयाँ पार करके असलियत तक पहुँच सकना लगभग असम्भव होगा। पहले महायुद्धमें अेक और भी अच्छा और आसान तरीक़ा निकाल लिया गया। अिसके ज़रिये लड़ाअीके खर्चेकी बड़ी बड़ी रक़में दान खाते लिख दी गअीं। यह 'दान' भारत सरकारने दिया और भारत सरकार व्हाअिट हॉलका अेक मातहत महकमा मात्र थी। अिस तरहसे जो बात दर असल क़र्ज़ लेकर मुकर जानेकी थी, अुसीको अीमानदार और प्रतिष्ठाका जामा पहना दिया गया।

हिन्दुस्तानके रुपयेसे ग्रेट बिटेनका पेट भरनेकी योजनामें जो ताज़ा विकास हुआ अुसका नमूना हमें दूसरे महायुद्धमें मिलता है। अिस तरीक़ेमें यह दिखानेकी कोशिश की गअी है कि अिक़रारनामा अीमानदारीसे हुआ है। अिसमें देशसे जो माल ले जाया गया अुसके बदलेमें रसीद दे दी गअी, मगर हमारे देशको अुसके अुधार दिये हुअे मालका मुनाफ़ा नहीं होने दिया गया। यह कितना आसान तरीक़ा है। रिज़र्व बैंकके क़ानूनमें अेक कसर है।[1] चलनके नोटोंकी पुश्तीके नियममें पासा, जिसका असली मूल्य होता है और पौण्डके काग़ज़ जिनमें सिर्फ़ ग्रेट ब्रिटेनकी साख होती है अिस क़ानूनसे अेक ही दर्जेमें रख दिये गये। यह अर्थनीतिके अच्छे अुसूलोंके ख़िलाफ़ है। अिस सूक्ष्म नियमका फ़ायदा अुठाकर बेशुमार नोट चलनमें डाल दिये गये हैं। 'स्टर्लिंग सिक्यूरिटी'का बड़ा नाम देकर हज़ारों करोड़की काग़ज़ी रसीदें रिज़र्वबैंक ऑफ़ अिण्डियामें रख दी गअीं और अुतनी ही रक़मके चलनके नोट छाप दिये गये।

---

१. रिज़र्व बैंक ऑफ़ अिण्डिया अैक्टकी दफ़ा ३३, अुपधारा २में जहाँ चलनकी पुश्तीकी चर्चा की गअी है, लिखा है कि सारी पूँजीका कमसे कम $\frac{२}{५}$ सोनेके सिक्कों, सोनेके पासों या पौण्डके काग़ज़ोंमें होगा।

अिस तरहसे क्रय-शक्ति आसानीसे तैयार करके अुससे अनाज, पाट, चाय वग़ैरा क़ीमती जिन्सें सुभीतेके कण्ट्रोल भावसे जुटा दी गअीं और युनाअिटेड किंगडम कमर्शियल कॉरपोरेशन नामकी ख़ास तौरपर बनाअी गअी सरकारी आढ़तके मारफ़त देशसे बाहर भेज ही गअीं। अिस तरक़ीबसे ग्रेट ब्रिटेनने रुक्के लिख लिखकर बेपारी जिन्सें ले लीं और हिन्दुस्तानको अपनी पैदावार बिना ब्याज अुधार देनी पड़ी। हमारे नोटोंका चलन फ़ुलावट करके शुरूकी मात्रासे सात गुनेसे भी ज़्यादा कर दिया गया है, मगर अुस हिसाबसे बाहरसे मँगाकर या भीतरी पैदावार बढ़ाकर जिन्सोंकी मात्रा नहीं बढ़ाअी गअी। अिसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे देशमें फ़ुलावटकी हालत अैसी पहले कभी नहीं हुअी थी। जिन स्टर्लिंग सिक्यूरिटियोंके बहुत जमा हो जानेसे भारत सरकारका पावना अितना बन गया अुनका ज़िक्र करते हुअे ब्रिटिश अर्थ मंत्रीने कॉमन्स सभामें ध्यान दिलाया था कि भारत सरकारकी अुदारतासे ब्रिटिश ख़ज़ानेको बहुत राहत मिली है! करोड़ों बेज़बान और भूखे लोगोंको नुक़सान पहुँचाकर यह अुदारता .ख़ूब रही!

## यूनाअिटेड किंगडम कमर्शियल कारपोरेशनके कारनामे

अिस बड़े आर्थिक कारबारमें यूनाअिटेड किंगडम कमर्शियल कारपोरेशनने जो कारनामे किये अुनके बारेमें अिस संस्थाके सभापति सर फ्रांसिस जोज़फ़ने लन्दनमें कहा था—" जब जून १९४०में कारपोरेशनने हिन्दुस्तानमें काम शुरू किया तब बहुत क़िस्मका माल मध्यपूर्वमें पहुँचाना ज़रूरी था . . . हिन्दुस्तान मित्र राष्ट्रोंका अुस वक़्त माल पहुँचानेका अेक ख़ास अड्डा था। भारत सरकारकी मददसे कारपोरेशनने जिस सामानकी सख़्त ज़रूरत थी वह जल्दी ही वहाँसे ले लिया। हिन्दुस्तानके गेहूँको जल्दी ही जहाज़ोंद्वारा भेजकर अीरानको १९४१के वसन्तमें और शुरूकी गरमियोंमें अकालके कष्टोंसे बचा लिया गया। अीरानको हिन्दुस्तानसे शक्कर-चाय-जैसी .ख़ूराककी चीज़ें, कपड़ा वग़ैरा तैयार माल और कच्चा माल मिल गया। जो माल जहाज़ोंके ज़रिये भेजा गया, अुसमें मिक़दारमें हज़ारों टन सीमेण्टसे लगाकर दवाअियोंके छोटे छोटे पारसल तक थे। मध्यपूर्वमें सीरिया और फ़िलस्तीन दूसरे देश थे जहाँ हिन्दुस्तानसे लेकर माल भेजा

गया। तुर्कीको लोहा, फ़ौलाद, सूत, टसरका कपड़ा, पाटके थैले, रस्सियाँ और कच्चा चमड़ा मिला। . . . यह स्पष्ट था कि रूसकी कुछ ज़रूरतें हिन्दुस्तान पूरी कर सकता था। अिसलिअे जिन्सोंकी लम्बी फ़ेहरिस्त बनाकर अुनकी माँग फ़ौरन् भेज दी गअी। सबकी मात्रा बड़ी बड़ी थी और अुन्हें जल्दी मुहैया करना था। अिस सूचीमें अैसी अैसी चीजें थीं जैसे टाटके थैले, पाटकी रस्सी, सूती केनवास, कच्चे चमड़े, चपड़ी, चाय, मूँगफली, तम्बाकू और काला सीसा। दर असल कितने कितने टन माल भेजा गया, अिसकी विगत देना तो सम्भव नहीं है, मगर रूसके लिअे हिन्दुस्तानमें कितना लम्बा-चौड़ा व्यापार किया गया अिसका अन्दाज़ अिस अेक बातसे लग सकता है कि हालमें अेक ही मांग १ करोड़ १० लाख टाटके थैलोंकी की गअी थी।"

यह अहमदकी टोपी महमूदके सरपर रखना हुआ। हम अीरानको अकालसे बचायें, मगर जिस हिन्दुस्तानको पहले ही खाने और पहननेको कम मिलता है वह अैसी जगह नहीं है जहाँसे यह .ख़ूराक और यह सारा क़ीमती सामान काग़ज़ी पुरज़ोंके बदलेमें छीन लिया जाय और वह भी सरकारके मुक़र्रर किये हुअे दामोंपर! हिन्दुस्तानको बदलेमें कोअी जिन्स नहीं मिली। यह अेक बात ही फुलावटके लिअे काफ़ी थी, क्योंकि यह जो माल बाहर भेजा गया सो कोअी फ़ालतू पैदावार नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर देशके मामूली ज़खीरेमेंसे लिया गया था। कुछ भी हो, आधा भूखा और आधा नंगा हिन्दुस्तान वह स्थान नहीं था जिसे अपना पेट काटकर ग्रेट ब्रिटेनको रुपयेकी अर्थनीतिसे मदद देनेको कहा जाय।

हिन्दुस्तानका काग़ज़ी सिक्का ग्रेट ब्रिटेनकी लड़ाअीकी खरीदारियों और खर्चोंकी क़ीमत चुकानेके लिअे बढ़ा दिया गया था और अिसके लिअे गवर्नर जनरलके फ़रमान जारी कर करके साधारण अंकुश दूर कर दिये गये थे।

## पौंडके काग़ज़की बेसलामती

जैसा हम पहले ही कह चुके हैं, 'स्टर्लिंग सिक्यूरिटीज़' सिर्फ़ ग्रेट ब्रिटेनकी साखकी निशानी है और अेक तरहसे खालिस रुक्के हैं। रुक्केकी क़ीमत रुक्का देनेवालेकी साखपर निर्भर होती है और साख क़र्ज़ लेनेवालेके लेने और देने पर आधार रखती है। अिस मामलेमें

ग्रेट ब्रिटेन ऋणी था । वह हर साल लड़ाअीपर औसत ५०००० लाख पौण्डके हिसाबसे खर्च करता रहा है और अिस ज़बरदस्त खर्चको पूरा करनेके लिअे अुसे मजबूर होकर पूँजी निकालनेका कार्यक्रम रखना पड़ रहा है और अुसे अपनी हज़ारों करोड़की विदेशी सिक्यूरिटियोंको भुनाना पड़ा है । यह दर असल गिरती हुअी साखकी बहुत बुरी हालत है । अैसे ऋणीके रुक्के जिसकी स्टालिंग सिक्यूरिटियोंपर लड़ाअीके बाद बरसों तक भी ब्याज मिलनेकी सम्भावना न हो, किस कामके ? अगर अिस पावनेपर रुपया न मिल सके, जैसा कि ग्रेट ब्रिटेनके रुपयेवाले लोग चाहते हैं, तो हिन्दुस्तान विदेशोंसे माल लेनेके लिअे अुसे काममें नहीं ले सकता । ले सकता है तो ग्रेट ब्रिटेनकी सुविधा और अिच्छाके अनुसार ही ले सकता है । अिस तरहसे ग्रेट ब्रिटेनका रुपये पैसेका सुभीता करनेके लिअे हिन्दुस्तानकी राजनीतिक पराधीनताका बेजा फ़ायदा अुठाकर अुसे जो चीज़ हक़से मिलनी चाहिये, अुससे वंचित रखा गया है ।

## क्रयशक्तिकी पायेदारी

पायेदार सिक्केकी ज़रूरत हमारे देशके लिअे बहुत बड़ी है । हमने देख लिया कि चलनके नोटोंकी मात्रा हमारी ज़रूरतोंका खयाल किये बिना बढ़ाअी जा रही है । अिससे रुपयेकी क्रयशक्तिमें भारी अुतार-चढ़ाव होता है । अुद्योगवाले देशोंकी बात दूसरी है । खेतीवाले देशको विनिमयका अैसा ज़रिया चाहिये जिसकी ठोस पुश्ती हो, ताकि क्रयशक्ति स्थायी रहे । अिसका कारण यह है कि अुद्योगवाले देशोंमें चलनके सिक्के या माध्यमके मामलेमें समयका कोअी खास महत्त्व नहीं होता । अेक पूँजीपतिका माल बिकते ही अुसे दाम मिल जाते हैं और वह तुरन्त अपने बैंकको दे देता है । मज़दूरको मज़दूरी मिल जाती है और वह अुस क्रयशक्तिके बदलेमें काम आनेवाली चीज़ें हफ्ते या महीने भरके भीतर जुटा लेता है । अुससे पहले रुपयेकी क़ीमतमें कोअी फ़र्क़ नहीं पड़ता । अुधर, खेतीवाले मुल्कमें किसान अपनी पैदावार फ़सल कटनेके बाद बेचता है और चूँकि गाँवमें बैंककी सुविधा नहीं होती, अिसलिअे अुसे अपने मालके दामोंको अगली फ़सल कटने तक जैसे-तैसे बचाकर रखना पड़ता है । अिसलिअे किसानके लिअे अैसा माध्यम रखना ज़रूरी है

जिसकी अपनी क़ीमत हो और वह स्थिर हो और जिसे वह आसानीसे बटोरकर रख सके। अिस तरह किसानोंकी धन गाड़कर रखनेकी आदत कोअी अैसा दुर्गुण नहीं है जो ठीक न हो सके, बल्कि अैसी अनिवार्य आवश्यकता है जो अुनके मौसमी धन्धेके कारण पैदा होती है। धन गाड़कर रखना तभी बन्द हो सकता है, जब अनेक तरहकी सहयोग-समितियोंका बढ़िया संगठन हो जाय और वह पैदावारका माल लेकर बेंच दे और बीचके समयमें किसानोंको रुपया-पैसा देता रहे। जब तक हम देहाती आबादीके लिअे अैसी सुविधाअें नहीं कर देंगे तब तक ज़मीनमें धन गाड़कर रखनेसे अेक बुनियादी ज़रूरत पूरी होती रहेगी और अिस कामके लिअे सोना जुटाना ही पड़ेगा। धन गाड़नेका मौजूदा अर्थ-व्यवस्थामें क्या स्थान है, यह समझे बिना अुसकी निन्दा करना महज़ अज्ञान या बेदर्दी ज़ाहिर करता है।

हमारा देश खेतीवाला है। यहाँ माध्यमसे दो काम निकलते हैं —(क) अेक तो विनिमयके साधनका और (ख) दूसरा क्रयशक्ति बटोरकर रखनेके ज़रियेका। अक्सर यह पहलेसे दूसरा काम ज़्यादा निकलता है। हमारे यहाँके आम लोग बिना कमाअी आमदनी खानेके लिअे रुपया नहीं लगाते, अुन्हें अितनेसे सन्तोष है कि अुनकी पूँजी ज्यों की त्यों बनी रहे। अिसलिअे चलन नोटोंकी यह पुश्ती अुड़ जाय या अुनकी असली क़ीमत घट जाय तो वह हमारे देशके लिअे बड़े महत्त्वकी बात है। जर्मनी-जैसे बहुत अुद्योगवाले देशमें भी ज़रूरतके मारे लोगोंने धन गाड़कर रखनेका आसरा लिया था। जब फुलावट बहुत बुरी तरह बढ़ गअी, तब जर्मनीके लोगोंने अपना रुपया जल्दीसे जल्दी निकलवाकर जो जिन्स अुनको मिल सकी अुसीको जुटाकर आगे काम आनेके लिअे अपनी क्रयशक्तिको गाड़कर रख दिया। किसानों तक ने मशीनें और पैदावारके औज़ार जुटा लिये। ये अुनके कभी काम न भी आते, तो भी अिनसे आगेके लिअे अुनकी क्रयशक्ति बनी रह गअी। हमारे चलनके अिस कामपर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। अिस पहलूको मजबूत करनेके लिअे यह ज़रूरी है कि हमारे चलनकी असली क़ीमत क़ायम रखी जाय। अिसके लिअे नोटोंके बदले लोगोंके लिअे सोनेके रूपमें काफ़ी पुश्ती

रखी जाय या अुन्हें पासे मिलनेकी सहूलियत दी जाय। अिस क़िस्मके विनिमयके माध्यमके बजाय आजकल तो स्थायी रूपसे अैसे नोट जारी किये जाते हैं, जिनकी क्रयशक्ति बड़ी नापायेदार होती है।

अिस बातकी बड़ी चर्चा हुअी है कि हिन्दुस्तानको अिस लड़ाअीसे फ़ायदा हुआ है और वह पहलेकी तरह ग्रेट ब्रिटेनका क़र्ज़दार न रह कर साहूकार बन गया है। जब तक दुनियाकी मण्डियोंमें स्वतन्त्र रूपसे खरीदारी करनेकी स्थिति नहीं हो जाती, तब तक हिन्दुस्तानको अिस बातसे सन्तोष नहीं हो सकता कि हमारे लाखों देहातियोंने कष्ट अुठाकर और भूखों मरकर जो माल दिया है अुसका पावना कागज़के रूपमें लन्दनमें जमा रहे। असली जिन्सें देकर बहुत भारी क़ीमत चुकाअी गअी है, क्योंकि वे कण्ट्रोलके भावोंसे ली गअी हैं और अिस लेनदेनमें खुद माल पैदा करनेवालोंकी ज़रूरतोंपर कोअी ध्यान नहीं दिया गया। अिस तरह हमारे देशका पावना बननेमें भी हम ज़्यादा ग़रीब हुअे हैं। यह भाग्यकी बलिहारी है! हम अैसे साहूकार हैं, जो अपने क़र्ज़दारोंकी मर्ज़ीपर निर्भर हैं।

पिछले सात सालके भीतर ब्रिटेनको जो माल और लड़ाअीका सामान दिया गया है, अुसके बदलेमें सैंतीस सौ करोड़ रुपया हिन्दुस्तानके खातेमें जमा किया गया है। अिसमेंसे चार सौ करोड़ रुपया तो, जिसे 'सरकारी क़र्ज़' कहा जाता है, अुसके पेटे काट लिया गया है और सत्रह सौ करोड़ रुपया यह कहकर हमारे नामें लिखा गया है कि यह लड़ाअीके खर्चका हमारा हिस्सा है, हालाँकि सच बात तो यह है कि हिन्दुस्तान अिस लड़ाअीमें कभी पड़ा ही नहीं। अिस सबके बाद जो सोलह सौ करोड़ रुपया बाकी बचा, अुसके बारेमें अब समझौतेसे फ़ैसला करनेकी कोशिश हो रही है।

### ग़बन

**डॉलर कोष:** लेकिन ग्रेट ब्रिटेनको अपना रद्दी क़ाग़ज़ स्टर्लिंग सिक्योरिटीज़के रूपमें गिरवी रखकर और सैंतीस सौ करोड़ रुपया खींचकर ही सन्तोष नहीं हुआ, अुसने हिन्दुस्तानके खानगी लोगोंके पास डॉलरके रूपमें और पौण्डके क़ाग़ज़के सिवा दूसरे रूपमें जो सम्पत्ति थी, अुसे

भी हड़प लिया। अिस सारे मालमतेपर ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा करके अुसे ग्रेट ब्रिटेनके लाभके लिअे लन्दनमें अेक डॉलर कोषमें रख दिया गया। आज तक हमें यह पता नहीं है कि हिन्दुस्तानसे लूटा हुआ कितना रुपया अिस डॉलर कोषमें है।

## ६

# अुपसंहार

हमने अीस्ट अिण्डिया कम्पनीके १८ वीं सदीके आर्थिक गुरुघण्टाल लॉर्ड क्लाअिवसे लगाकर २० वीं सदीके दूर दूर तक फैले हुअे ब्रिटिश साम्राज्यके आर्थिक गुरुघण्टाल लॉर्ड केनीज़ तक लम्बा सफ़र कर लिया। अिन लोगोंने जितने भी आर्थिक पाप हो सकते हैं, सब किये। फ़र्क़ अितना ही था कि लॉर्ड क्लाअिवमें भले ही अपने बादके प्रतिनिधि (लॉर्ड केनीज़) की-सी सभ्य भाषा न रही हो, मगर अुसके साहसके कामोंमें ताज़गी थी। अिन लोगोंकी नीति कमज़ोर जातियोंके साधनोंका दुरुपयोग करके अुन्हें बेहयाअीके साथ चूसते रहनेकी ही रही है। यह साम्राज्य लोभसे पैदा हुआ, लूटसे मोटा हुआ और झूठका जामा पहनकर शानदार बना है।

सन् १९३१ में करॉंची कॉंग्रेसके मौक़ेपर अेक सिलेक्ट कमिटी अिस वास्ते मुक़र्रर हुअी थी कि वह अीस्ट अिण्डिया कम्पनी और हिन्दुस्तानके अंग्रेज़ी राज्यके लेन-देनकी और भारतके "सरकारी ऋण"की छानबीन करे और रिपोर्ट पेश करे कि आयन्दा आर्थिक भार कितना हिन्दुस्तान अुठाये और कितना अिग्लैण्ड। पूरे अध्ययनके लिअे तो पाठकोंको कमेटीकी रिपोर्ट ही पढ़नी चाहिये, परन्तु यहाँ अुसकी आख़िरी सिफ़ारिशें दी जा सकती हैं:

"जबसे अीस्ट अिण्डिया कम्पनीको राजनीतिक सत्ता मिली और हिन्दुस्तानपर अंग्रेज़ोंका कब्ज़ा हुआ, तबसे ग्रेट ब्रिटेनकी दौलत और अिज़्ज़त बराबर बढ़ती रही है। दूसरी तरफ़ हिन्दुस्तानके लिअे यह

नतीजा हुआ है कि हिन्दुस्तानके अुद्योग या तो नष्ट कर दिये गये या दबा दिये गये और हिन्दुस्तान ग्रेट ब्रिटेनके तैयार माल और दूसरी पैदावारके लिअे अेक मण्डी बन गया। अिस मण्डीका विकास न होता और ब्रिटेनके अुद्योगोंको बढ़ानेके काममें हिन्दुस्तानका धन अिस्तेमाल न किया जाता, तो ब्रिटेनकी आज-जैसी हालत कभी नहीं हो सकती थी। हिन्दुस्तानमें अंग्रेज़ोंको सब तरहकी सिविल और फ़ौजी नौकरियाँ मिलनेका लम्बा-चौड़ा क्षेत्र मिल गया। और अगर तनखाहों और पेन्शनोंका दिया हुआ सारा रुपया जोड़ा जाय तो अुनका आँकड़ा भी बहुत भारी होगा। ब्रिटेनको सचमुच जो आर्थिक लाभ हुआ है अुसके अलावा वह दुनियाकी जो अेक बड़ी ताक़त बन गया है, अिसका मुख्य कारण भी हिन्दुस्तानका अुसके हाथमें होना ही है। ये बातें ख़ुद ही अिस बातके लिअे काफ़ी कारण हैं कि हर नीति और न्यायके खयालसे सरकारी ऋणके रूपमें अिस वक़्त जो भी कर्ज़ा है वह सब हिन्दुस्तानके बजाय ग्रेट ब्रिटेनपर पड़ना चाहिये।"[१]

**और लीजिये :**

"न्यायके हर सिद्धान्तका तक़ाज़ा है कि अगर हिन्दुस्तानको राष्ट्रीय स्वराज्यका नया दौर शुरू करना है और कुछ भी अुन्नति करनी है, तो अुसे आज़ादीके साथ और बिना किसी भारके काम शुरू करना चाहिये। हिन्दुस्तान अब और ज़्यादा कर नहीं सह सकता। अिसलिअे हिन्दुस्तानकी तरक़्क़ी अिसी तरह हो सकती है कि राष्ट्रकी आमदनी राष्ट्रके कामोंमें लगायी जाय और देशके सिविल और फ़ौजी बन्दोबस्तपर राष्ट्रीय खर्च अपनी ज़रूरतके माफ़िक घटाया जाय और जो सरकारी ऋण हिन्दुस्तानकी भलाअीके लिअे नहीं लिया गया हो अुसके भारसे अुसे मुक्त किया जाय; तभी अैसी बचत हो सकती है, जो हिन्दुस्तानकी भलाअीके कामोंमें यानी शिक्षा, सफ़ाअी और राष्ट्रकी अुन्नतिके दूसरे अुपायोंमें लगायी जा सकती है।"[२]

---

१. रिपोर्ट पृ० ६०–६१

२. कांग्रेस सिलेक्ट कमेटीकी रिपोर्ट देखिये।

अिस कमेटीने, हिन्दुस्तानपर जो नीचे लिखे ग़लत ख़र्चे डाल दिये गये हैं, अुनकी तरफ़ ध्यान दिलाया है :

| साल | दावेका विषय | रक़म करोड़ोंमें | |
|---|---|---|---|
| १८५७ से पहले | कम्पनीकी बाहरी लड़ाअियाँ | ३५,००० | |
| | कम्पनीकी पूँजीका ब्याज | १५,१२० | ५०,१२० |
| १८५७ | 'ग़दर'का ख़र्च | | ४०,००० |
| १८७४ | कम्पनीकी पूँजीका ब्याज | १०,०८० | |
| | अीस्ट अिण्डिया कम्पनीकी पूँजीके हिस्सोंकी मुक्ति | १२,००० | २२,०८० |
| १८५७–१९०० | बाहरी लड़ाअियोंका खर्च | ३७,५०० | |
| १९१४–१९२० | यूरोपकी लड़ाअीमें दान | १,८९,००० | |
| | ,, खर्च | १,७०,७०० | ३,९७,२०० |
| १८५७–१९३१ | फुटकर खर्च | २०,००० | |
| | बर्माके बारेमें | ८२,००० | १,०२,००० |
| १९१६–१९२१ | अुल्टी हुण्डियोंका घाटा | | ३५,००० |
| | रेल्वे कम्पनियोंको सरकारने लिया अुसका मुनाफ़ा दिया | | ५०,००० |
| १९१६–१९२१ | लड़ाअीके कामकी रेलोंका खर्च | | ३३,००० |
| | | करोड़ | ७,२९,४०० |

अूपरके दावोंमें फ़ौजी ख़र्चका कोअी हिस्सा शामिल नहीं है, जिसके लिअे कमेटीका कहना है कि साम्राज्यके खज़ानेके नाम लिखा जाना अुचित है। अेक सदस्यने रिपोर्टमें अेक नोट[1] जोड़ा है, जिसमें अुनके हिसाबसे यह रक़म ५४०·१३ करोड़ रुपये होती है। यह रक़म कम बताअी गअी है क्योंकि यह फ़ौजी खर्चके चौथाअीके लगभग है, जब कि मि. रेम्ज़े मैक्डोनल्डको .खुद विश्वास है कि हिन्दुस्तानकी कमसे कम आधी सेना साम्राज्यकी सेना है और अुनका सुझाव है कि अुसका खर्च साम्राज्यके खज़ानेसे दिया जाना चाहिये।

---

१. कांग्रेस सिलेक्ट कमेटीकी रिपोर्ट देखिये

अिसके सिवा जिस ब्याजका दावा किया गया है वह वापस नहीं लौटाया गया और रिपोर्टके दूसरे नोटमें हिसाब लगाकर बताया गया है कि कुल १०५० करोड़ रुपयेमेंसे ५३६·०२ करोड़ रुपया वापस दिया जाना चाहिये। अिस तरह हिन्दुस्तानके नाम जो रक़में बेजा तौरपर लिखी गअी हैं अुनका जोड़ होता है:

| | |
|---|---|
| अूपरके हिसाबके अनुसार | ७२९·४ करोड़ |
| सालाना फ़ौजी खर्चेका हिस्सा | ५४०·१३ करोड़ |
| बेजा तौरपर दिया गया ब्याज | ५३६·०२ करोड़ |
| | १,८०५·५५ |

यह १८०५½ करोड़ रुपया हिन्दुस्तानी करदाताके मत्थे मढ़ा गया है, लेकिन यह पड़ना चाहिये ब्रिटिश खज़ानेपर। अिन खर्चोंमेंसे ज़्यादातर खर्चे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति और अुससे पैदा होनेवाली लड़ाअियोंके कारण हुअे हैं। यहाँ तफ़सील तो नहीं दी जा सकती, लेकिन हम कहेंगे कि पाठक कांग्रेस कमेटीकी रिपोर्ट ज़रूर देखें। ग़लत तौरपर हमारे नाम लिखी गअी अिन रक़मोंपर हम ५० करोड़ रुपया सालाना तो ब्याज ही दे रहे हैं। जे० रेम्ज़े मेक्डोनल्ड कहते हैं— "हिंदुस्तान मेज़ें बाहर अिसलिअे नहीं भेजता है कि अुसी हिसाबसे कुर्सियाँ बाहरसे मँगवाकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले; वह मेज़ें कर्ज़ चुकानेकी खातिर बाहर भेजता है।" जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं— "जो देश बाहरी मुल्कोंको नियमित रूपसे रुपया देता है वह दिया हुआ रुपया तो खाता ही है, अिससे भी ज़्यादा नुकसान अुसका यह होता है कि विदेशी चीज़ोंके बदलेमें अुसे अपनी पैदावार सस्तेमें देनी पड़ती है।" अिसका और भी बुरा नतीजा तब होता है जब साहूकार देशके हाथमें कर्ज़दार मुल्ककी अर्थनीति, चलन और विनिमयकी नीति होती है और माल मँगवानेका अधिकार भी अुसीके पास होता है। हिन्दुस्तानका यही हाल हुआ है। अुसके हाथमें यह शक्ति नहीं थी कि वह अपने रुपयेका पूरा बदला वसूल कर सके; और अुसकी गर्दनमें ये झूठी ज़ंजीरें लटकाये रखकर ब्रिटेनको यह आशा है कि वह वर्षों तक हिन्दुस्तानका गला दबाये रख सकेगा। अगर हिन्दुस्तानको अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियोंमें अपनी सौदा करनेकी ताक़त फिरसे प्राप्त

करनी हो, तो अुसे यह बेहोश करनेवाली ज़ंजीरें तोड़कर अपना हक़ माँगना होगा।

जो फ़ौजी ख़र्च हिन्दुस्तानपर डाले गये हैं, अुनके बारेमें मि० मेक्डोनल्ड लिखते हैं — "बेशक, हिन्दुस्तानके साथ अिस मामलेमें न्यायका बर्ताव नहीं किया गया। जो सैनिक कार्रवाअियाँ ज़्यादातर साम्राज्यवादी थीं, अुनका ख़र्चा अुसे बर्दाश्त करना पड़ा है।"[1] "जब हमने साम्राज्यके दूसरे हिस्सोंमें फ़ौजें रखीं, तो अुपनिवेशोंपर अुनका ख़र्च नहीं डाला। लेकिन हिन्दुस्तानमें तो हमारा कोअी हाथ पकड़नेवाला नहीं है। जब कम्पनीका राज्य था, अुसने ग्रेट ब्रिटेनसे फ़ौज अुधार ली थी और अुसने अुस फ़ौजके हिन्दुस्तानमें रहनेका ख़र्च ही नहीं दिया, बल्कि अुसे वहाँ ले जानेकी भी क़ीमत चुकाअी। जब कम्पनीने अधिकार ताजको सौंप दिया, तब भी सेना "अुधार देने"का रिवाज क़ायम रखा गया क्योंकि यह झूठा रिवाज ग्रेट ब्रिटेनके ख़ज़ानेके लिअे सुविधाजनक था। १९००में आर्थिक कमीशनकी रिपोर्टके कारण ब्रिटिश सरकार अब १३०,००० पौण्ड सालाना देती है। यह रक़म फ़ौजोंके भेजे जानेका आधा ख़र्च मानी जाती है। अदनके फ़ौजी ख़र्चेका आधा रुपया, यानी अेक लाख पौण्ड ब्रिटिश ख़ज़ानेपर लगाया जाता है। बस, अिसके सिवा सारा ख़र्च हिन्दुस्तान देता है। अिस तरह हिन्दुस्तानके साथ अेक आज़ाद हुकूमतका-सा बर्ताव होता है, लेकिन राज अुसपर हम करते हैं और अुसकी फ़ौजी नीति हमारे हाथमें है। वह हमसे कुछ सिपाही अुधार ले लेता है और अुनका ख़र्च दे देता है। यह व्यवस्था बहुत ही असन्तोषजनक है।" आगे चलकर वे बाहरी लड़ाअियोंके विषयमें और कहते हैं — [2]"अिस कमीशनने अपनी रिपोर्ट १९००में दे दी। आशा है अुसने अेक और भी बड़ी शिकायत दूर कर दी। सरहदी लड़ाअियोंका और बर्माकी तरह दूसरे देशोंको मिलानेकी लड़ाअियोंका और अबीसीनियाकी मुहिमका ख़र्च हिन्दुस्तानी करदाताओंने दिया है। अफ़गान युद्धके ख़र्चेके २ करोड़ १० लाख पौण्डमेंसे सिर्फ़ ५० लाख

---

१. जे. आर. मेक्डोनल्डकी 'गवर्नमेण्ट ऑफ़ अिण्डिया' पृ० १५४

२. " " पृ० १५५

पौण्ड साम्राज्यके खजानेने दिये। ये मुहिमें दर असल साम्राज्य-नीतिके काम हैं और अुनका खर्च हिन्दुस्तानपर बिलकुल न पड़ना चाहिये।" श्री गोखले साहबने अेक बार स्थितिको अिस तरह बयान किया था —"चीन, अीरान, अबीसीनिया और दूसरी मुहिमोंके लिअे अिंग्लैण्डने साम्राज्य-नीतिके खयालसे हिन्दुस्तानसे पिछले समयमें फ़ौजें अुधार ली हैं और अिन सब अवसरोंपर अिन सेनाओंका साधारण खर्च हिन्दुस्तानसे लिया गया है, अिंग्लैण्डने सिर्फ़ ग़ैरमामूली खर्च दिया है। अुधर जब हिन्दुस्तानको अिंग्लैण्डसे फ़ौज माँगनी पड़ी, जैसा कि १८४६की सिन्धकी मुहिम, १८४९की पंजाबकी मुहिम और १८५७के ग़दरके मौक़ेपर हुआ, तब अिन आदमियोंका पाअी-पाअी खर्च, साधारण और असाधारण, यहाँ तक कि अुनकी भरतीका खर्च भी हिन्दुस्तानसे अैंठ लिया गया।" कमीशनकी रिपोर्टने अिस खास शिकायतको दूर कर दिया, लेकिन अन्यायपूर्ण व्यवहारको स्वराज्य ही पूरी तरह दूर करेगा और वही अैसी मुहिमोंका जो साम्राज्यके लिअे हों, खर्च भी साम्राज्यके ख़ज़ानेसे वसूल करेगा।

यह सुझाया गया है कि अिन १८ करोड़का अेक हिस्सा चूँकि चुका दिया गया है, अिसलिअे अुस हिस्सेके बारेमें हमें कोअी सवाल अुठाना नहीं चाहिये। साफ़ विचार न होनेके कारण अिस तरहकी अज़ीब दलील दी जाती है। अगर कोअी व्यापारी किसी ग्राहकके नाम १८००) रु. लिख देता है और अिसका कारण ग्राहक पूछे, अिससे पहले व्यापारी अुसपर ब्याज भी लेता रहा हो और मूल रक़म पेटे ८००) रु. भी ले चुका हो, तो क्या जिस वक़्त ग्राहक हिसाब माँगे, व्यापारीको यह कहनेका हक़ है, "चूँकि मूलधनके मद्दे मैंने आपसे रुपया ले लिया है, अिसलिअे अब हम बाक़ी रक़मकी विगत ही देखेंगे और जो ८००) रु. चुकाया जा चुका है, अुसके बारेमें विचार करनेकी ज़रूरत नहीं"? अगर हिन्दुस्तानके ऋणका कोअी हिस्सा अैसा है जो चुका दिया गया है तो वह चुकाया किसने? वह हिन्दुस्तानी करदाताने चुकाया है और अगर अुससे बेजा तौरपर लिया गया है तो अुसका मावज़ा देना पड़ेगा।

१९३१की गोलमेज़ परिषद्में सरकारी ऋणोंके बारेमें बोलते हुअे गांधीजीने कहा था —"कांग्रेसकी ज़ोरदार राय है कि आनेवाली सरकारको

जा ज़िम्मेदारियाँ अुठानी पड़ें, अुनके हिसाबकी अच्छी तरह निष्पक्ष जाँच-पड़ताल होनी चाहिये ।"

अिन १८ सौ करोड़में ३७ सौ करोड़ और जोड़े जाने चाहियें, जो १९४६ तक पिछले सात सालमें हिन्दुस्तानसे अैंठ लिये गये हैं । अिस तरह झगड़ा कुल ५५ सौ करोड़ रुपयोंका है ।

## चुकानेकी शक्ति

ग्रेट ब्रिटेनकी चुकानेकी शक्तिके बारेमें हम कह सकते हैं कि ग़रीब हिन्दुस्तानकी अिस भारी बोझको सहन करनेकी शक्तिमें, जैसा कि अुसने पिछले सात सालमें किया है, और ग्रेट ब्रिटेनकी वापस अदा करनेकी शक्तिमें कोअी तुलना नहीं हो सकती । ग्रेट ब्रिटेनकी सालाना आमदनी ९ सौ करोड़ पौण्डसे अूपर है और अुसपर हमारा ऋण अिस आमदनीका बहुत छोटा हिस्सा होगा । हमें याद रखना होगा कि यह ३७ सौ करोड़का पावना ब्रिटेनके अपने आदमियोंका बनाया हुआ है, अुन्होंने ही क़ीमतें लगायी हैं और हिन्दुस्तानके बाज़ार भावसे बहुत नीची कण्ट्रोलकी दरें काममें ली हैं । बहुत बार तो लड़ाअीके ज़मानेमें गवर्नर जनरलको जो निरंकुश सत्ता मिली हुअी थी, अुसीके ज़ोरसे माल ले लिया गया और अिस बातका भी कोअी लिहाज़ नहीं किया गया कि लड़ाअीके ज़मानेमें सरकारने रेल्वे वग़ैरह जैसे भारी सामानको जो काममें लिया अुसकी कितनी ज़बर्दस्त घिसाअी और टूट-फूट हुअी है। जब माल जबरन लिया गया तो हिन्दुस्तानके लोगोंकी निरी आवश्यकताओंका भी कोअी प्रबन्ध नहीं किया गया । सन् १९४३ के बंगालमें जो ३० लाखसे ज्यादा जानें गअीं, वे अिस बातका प्रमाण हैं । अगर हमारे-जैसे ग़रीब मुल्कका जिन्सोंके कमसे कम भावसे और जबरन सात सालके भीतर कमसे कम भी गिनें तो ३७ सौ करोड़ रुपयेका पावना अिकट्ठा कराया जा सकता है, तो ग्रेट ब्रिटेन जिसकी राष्ट्रीय आमदनी ९ सौ करोड़ पौण्ड सालाना है, लम्बी मियादके समझौतेका दावा कैसे कर सकता है ? जैसा कि प्रो० जी० डी० अेच० कोल कहते हैं : "यह अजीब दुनिया है जिसमें अेक मालदार और

आगे बढ़े हुअे देशको अपनेसे बहुत ज़्यादा ग़रीब मुल्कसे अुसका ऋण घटाने या लम्बी मियादमें चुकानेकी प्रार्थना करनी पड़े।"

## जाँच पड़तालकी ज़रूरत

अिस छोटेसे विवेचनसे पता चल जायगा कि अिंग्लैण्डने हिन्दुस्तानके साथ आर्थिक व्यवहारमें सन्देह भरे तरीक़ोंसे काम लिया था और १६ सौ करोड़ रुपयेके जिस "पौण्ड पावने"का अब फ़ैसला करनेकी कोशिश की जा रही है वह कोअी निश्चित और हिसाब साफ़ करनेवाला बक़ाया नहीं है। वह अैसा बक़ाया है जिसका चालू हिसाब ग्रेट ब्रिटेनने रखा है और हम हिन्दुस्तानियोंकी तरफ़से कोअी जाँच पड़ताल होने नहीं दी गअी है। अिसलिअे अिस हिसाबकी कोअी आर्थिक ज़िम्मेदारी अुठानेसे पहले यह ज़रूरी होगा कि अेक निष्पक्ष अदालतके द्वारा ख़ुद अिस चालू खातेकी पूरी तरह जाँच पड़ताल करा ली जाय। यह चालू खाता क्लाअिवके ज़मानेसे शुरू होता है और अिसकी कभी सार्वजनिक जाँच नहीं हुअी है। अिसलिअे हमें अुम्मीद है कि हिन्दुस्तानकी आज़ाद राष्ट्रीय सरकार ग्रेट ब्रिटेनसे कोअी मालमता ले या बड़ी नौकरियोंके बारेमें कोअी और ज़िम्मेदारी अुठाना मंजूर करे अुससे पहले अिस चालू खातेकी अच्छी तरह छानबीन करनेके लिअे अेक निष्पक्ष न्यायालय मुक़र्रर करेगी। १९३१ की कांग्रेस सिलेक्ट कमेटीने अिसी तरहकी निष्पक्ष अदालत मुक़र्रर करनेकी सिफ़ारिश की थी।

आखिरी तौरपर तय की हुअी हिन्दुस्तानकी बाक़ी रक़म, जो सोना पिछले २० सालमें हिन्दुस्तानसे ले जाया गया है, अुस सारेको या अुसके कुछ हिस्सेको लौटाकर या कुछ हिन्दुस्तानमें जो ब्रिटिश मिल्कियत है अुससे चुकाअी जा सकती है। बहुतसी सिंचाअीकी योजनाअें भी हैं जो ४५० करोड़ तक पहुँचती हैं। बहुतसी मशीनरी और सामान भी बाहरसे मँगवाना पड़ सकता है। ये चीजें भी ग्रेट ब्रिटेन दे सकता है। कुछ भी हो, हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो कुछ पावना हमें मिले वह हिन्दुस्तानके देहातकी धरोहर समझी जाय।

अक्सर यह दावा किया जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन बहुत ज़्यादा मात्रामें भारी पूँजी देगा, तो अुसकी पैदावार और निर्यात व्यापारको

बड़ा धक्का लगेगा। यह तभी हो सकता है, जब पूँजी आमदनीमेंसे चुकाअी जाय। लेकिन ग्रेट ब्रिटेनके पास क़ाफ़ीसे ज्यादा पूँजीकी अैसी मदें हैं जिन्हें वह हिन्दुस्तानके हक़में तब्दील करा सकता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि ग्रेट ब्रिटेनके खातेमें अमरीकाके बैंकोंकी तिजोरियोंमें सोना पड़ा हुआ है। अिसके अलावा ग्रेट ब्रिटेनमें रेल्वेके प्रिफरेन्स शेयरों और डिबेंचरोंकी पूँजी आसानीसे भारत-सरकारके नाम बदलाअी जा सकती है। ग्रेट ब्रिटेनके पास लाखों टनके व्यापारी जहाज़ हैं। यह जायदाद भी लेना हिन्दुस्तानको मंजूर होगा, क्योंकि अुसे अपना व्यापारी जहाज़ोंका अुद्योग बढ़ानेकी चिन्ता है। अिस तरह अगर ग्रेट ब्रिटेनकी अपना क़र्ज़ चुकानेकी तैयारी हो, तो अुसमें अितनी आर्थिक और व्यापारी बुद्धि ज़रूर है कि वह अपने वाजिब क़र्ज़ चुकानेके अुपाय निकाल सकता है। किसी क़र्ज़दारको यह शोभा नहीं देता कि जब अुसे ज़रूरत पड़े तब तो वह अुधार ले ले और फिर बैठकर हिसाब करते वक़्त कठिनाअियोंका रोना रोये।

जैसे और जब यह मिल्कियत भारत सरकारको मिले, तब पौण्डके काग़ज़ जो लन्दनमें पड़े हैं वे अिस मिल्कियतकी दोनों तरफ़से मानी हुअी क़ीमत चुकानेके लिअे दिये जा सकते हैं और भारत सरकार या तो अिस मिल्कियतको हिन्दुस्तानियोंके नाम कर दे या खुद अपने पास रख ले और अिस तरह लगी हुअी पूँजीसे आमदनी करे। अिससे जो रुपया वसूल हो वह शहरोंमें बड़े बड़े कारखाने बनानेमें खर्च न करके देहातका कष्ट निवारण करनेके लिअे सिंचाअीकी योजनाओं, पीनेका पानी मुहैया करने, नहर और जलमार्ग बनाने पर खर्च करना चाहिये। ये और दूसरी अैसी ही बातें भी, जो समझौतेकी शर्तोंसे पैदा हों, अूपर सुझाअी हुअी निष्पक्ष अदालतके सामने रखी जा सकती हैं।